नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 174
दि. 29.03.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

एक महीने का युद्ध, वैश्विक बेचैनी: ईरान संकट ने दुनिया को अनिश्चितता के मुहाने पर ला खड़ा किया

वाशिंगटन। अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान के बीच जारी युद्ध को एक महीना पूरा हो चुका है, लेकिन हालात सामान्य होने के बजाय और जटिल होते जा रहे हैं। धमकियों, जवाबी हमलों और तीखी बयानबाजी के बीच कूटनीतिक समाधान की उम्मीदें धुंधली पड़ती दिख रही हैं। इस संघर्ष का असर केवल मध्य-पूर्व तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ चुकी है।

28 फरवरी को शुरू हुआ यह युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां हर दिन नई आशंकाएं जन्म ले रही हैं। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। मिसाइल और ड्रोन हमलों की यह श्रृंखला पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर रही है। स्थिति यह है कि एक महीने बाद भी न तो कोई पक्ष पीछे हटने को तैयार है और न ही बातचीत की दिशा में कोई ठोस प्रगति दिखाई दे रही है।

इस युद्ध का सबसे बड़ा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ा है। विशेष रूप से होर्मुज़ जलडमरूमध्य को लेकर बनी अनिश्चितता ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। यह जलमार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा वहन करता है। इसके आंशिक या पूर्ण रूप से बाधित होने की आशंका ने कच्चे तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है।

भारत के लिए यह स्थिति विशेष रूप से गंभीर है। देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 80 प्रतिशत तेल आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर आता है। ऐसे में यदि आपूर्ति बाधित होती है, तो न केवल ईंधन संकट पैदा हो सकता है, बल्कि इसका सीधा असर महंगाई, परिवहन और कृषि क्षेत्र पर भी पड़ेगा। यूरिया जैसे उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित होने से खाद्य उत्पादन पर भी दबाव बढ़ सकता है, जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ और बढ़ेगा।

खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों भारतीयों के सामने भी संकट खड़ा हो गया है। यदि युद्ध लंबा खिंचता है, तो वहां की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होंगी, जिससे रोजगार और प्रेषण धन

(रेमिटेंस) पर असर पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था में खाड़ी देशों से आने वाले रेमिटेंस की महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसे में इसमें गिरावट व्यापक आर्थिक प्रभाव डाल सकती है।

वैश्विक स्तर पर भी हालात चिंताजनक हैं। यूरोप पहले ही ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, और कतर से गैस आपूर्ति में संभावित बाधा ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। उद्योगों पर दबाव बढ़ रहा है और बिजली संकट गहराने की आशंका है। दूसरी ओर अमेरिका, जो ऊर्जा के मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भर है, वहां भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने घरेलू राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। जनता के बीच असंतोष बढ़ रहा है, जो राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकता है।

मानवीय दृष्टिकोण से भी यह युद्ध बेहद भयावह साबित हो रहा है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, अब तक एक दर्जन से अधिक देशों में 4500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। केवल ईरान में ही हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। लेबनान, इजरायल और अन्य खाड़ी देशों में भी बड़ी संख्या में हताहत हुए हैं। यह आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि यह संघर्ष अब एक क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले चुका है।

इस बीच, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी रणनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि उनके पास अब दो ही विकल्प बचे हैं—या तो वे कूटनीतिक रास्ता अपनाकर ईरान के साथ समझौता करें, या फिर सैन्य कार्रवाई को और तेज करें। लेकिन सैन्य कार्रवाई बढ़ाने का मतलब होगा एक लंबा और महंगा युद्ध, जिसका असर उनकी राजनीतिक छवि और भविष्य पर भी पड़ सकता है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप लंबे समय तक चलने वाले युद्ध से बचना चाहते हैं और बातचीत के जरिए समाधान तलाशने के पक्ष में हैं। हालांकि, व्हाइट हाउस के कुछ अधिकारी मानते हैं कि हालात इतने जल्दी सामान्य होने वाले नहीं हैं। दोनों पक्षों की आक्रामक रणनीति और बयानबाजी ने स्थिति को और पेचीदा बना दिया है।

अमेरिका ने इस युद्ध के पीछे अपने तीन प्रमुख लक्ष्य बताए थे—ईरान की मिसाइल क्षमता को कमजोर करना, उसे परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना और मध्य-पूर्व में अपने सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की 90 प्रतिशत मिसाइल क्षमता को नष्ट कर दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हमले अभी भी जारी हैं। इससे साफ है कि युद्ध का निर्णायक परिणाम अभी दूर है।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, राजनीति और मानव जीवन—हर स्तर पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है।

आज की स्थिति में सबसे बड़ी चिंता अनिश्चितता की है। कोई नहीं जानता कि यह युद्ध कब खत्म होगा और इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। कूटनीति और संवाद ही इस संकट से निकलने का एकमात्र रास्ता नजर आता है, लेकिन जब तक दोनों पक्ष अपनी-अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, तब तक शांति की राह मुश्किल बनी रहेगी।

एक महीने के इस युद्ध ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम एक और लंबे वैश्विक संकट की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाले दिन न केवल मध्य-पूर्व, बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य के लिए निर्णायक साबित होंगे।

ईरान की जंग: सिर कटा लेकिन हौसला नहीं झुका, एक महीने बाद भी तेहरान की रणनीति ने बदला युद्ध का पूरा समीकरण

तेहरान से उठती बारूद की गंध, ढह चुके सैन्य ठिकानों की तस्वीरें और शुरुआती हमलों में शीर्ष नेतृत्व के खत्म हो जाने के बावजूद ईरान जिस तरह इस युद्ध में डटा हुआ है, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों के साथ शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक महीने का पड़ाव पार कर चुका है, लेकिन जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि शुरुआती झटकों के बाद ईरान घुटनों पर आ जाएगा, वैसा कुछ भी होता नजर नहीं आया। उल्टा, तेहरान ने खुद को संभालते हुए इस युद्ध को एक नई दिशा दे दी है, जहां उसकी रणनीति सैन्य कमजोरी के बावजूद उसे मजबूत बनाकर खड़ा कर रही है। हमलों के शुरुआती घंटों में ही ईरान की सत्ता और सैन्य ढांचे को सबसे बड़ा झटका लगा। सुप्रीम लीडर से लेकर रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कई बड़े कमांडर तक इस हमले की चपेट में आ गए। यह किसी भी देश के लिए ऐसा वार होता है, जिससे उबरना लगभग असंभव माना जाता है। लेकिन ईरान ने यहां अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाई—उसकी संस्थागत व्यवस्था। सत्ता का केंद्रीकरण टूटने के बाद भी उसने तुरंत नई कमांड चेन खड़ी कर दी। फैसले लेने की प्रक्रिया को नीचे तक फैलाया गया, जिससे युद्ध केवल कुछ चेहरों पर निर्भर न रहकर एक सिस्टम के रूप में चलता रहा। यही वजह है कि नेतृत्व के नुकसान के बावजूद ईरान की सैन्य कार्रवाई थमी नहीं, बल्कि और तेज होती चली गई। तेहरान ने जवाबी हमलों में जिस तरह बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया, उसने यह साफ कर दिया कि उसकी युद्ध क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इजरायल के कई शहरों पर हमले हुए, जिनमें तेल अवीव जैसे अहम इलाके भी शामिल रहे। इन हमलों में क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल की खबरों ने इस संघर्ष की गंभीरता को और बढ़ा दिया। हर नए हमले के साथ यह संदेश दिया गया कि ईरान अभी भी जवाब देने की स्थिति में है और उसे पूरी तरह दबाना आसान नहीं होगा।

लेकिन इस युद्ध की असली कहानी केवल मिसाइलों और बमों की नहीं है, बल्कि उस रणनीति की है जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान की पकड़ इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा मोड़ बनकर सामने आई है। दुनिया के करीब 20 प्रतिशत तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है और यहां किसी भी तरह की रुकावट सीधे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। ईरान ने इसी बिंदु को अपनी ताकत बना लिया। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ीं, आपूर्ति बाधित हुई और इसका असर अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक महसूस किया जाने लगा। भारत जैसे देश, जो अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करते हैं, उनके लिए यह स्थिति और भी चिंताजनक बन गई। ईरान ने इस युद्ध को केवल अपने सीमित संसाधनों तक नहीं रखा, बल्कि उसने अपने सहयोगी नेटवर्क को भी सक्रिय कर दिया। लेबनान में हिजबुल्लाह ने मोर्चा तेज कर दिया, जबकि यमन के हूती विद्रोही भी इस संघर्ष में खुलकर सामने आ गए। इससे यह युद्ध एक देश के खिलाफ लड़ाई न रहकर पूरे क्षेत्र में फैला हुआ बहुस्तरीय संघर्ष बन गया है। अमेरिका और इजरायल के लिए यह स्थिति और जटिल हो गई है, क्योंकि अब उन्हें कई मोर्चों पर एक साथ ध्यान देना पड़ रहा है।

हालांकि यह भी सच है कि अमेरिका और इजरायल के हमलों ने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है। उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को गंभीर क्षति पहुंची है। कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने नष्ट हो चुके हैं और उसकी क्षमताओं को गहरा झटका लगा है। लेकिन इसके बावजूद ईरान की सेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का मनोबल टूटता नहीं दिख रहा। यही इस युद्ध का सबसे अप्रत्याशित पहलू है कि संसाधनों के नुकसान के बाद भी इच्छाशक्ति कायम है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका के रुख में भी बदलाव साफ नजर आ रहा है। शुरुआत में सख्त बयान और "रिजीम चेंज" की बात करने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ज्यादा सावधानी बरतते दिखाई दे रहे हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने की डेडलाइन बार-बार बढ़ाई जा रही है और ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर बड़े हमले टाले जा रहे हैं। इसके पीछे केवल सैन्य कारण नहीं, बल्कि घरेलू दबाव भी है। अमेरिका में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल की कीमतों में उछाल और शेयर बाजार की गिरावट ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। जनता और राजनीतिक वर्ग के भीतर यह सवाल उठने लगा है कि यह युद्ध कितने लंबे समय तक चलेगा और इसकी कीमत कौन चुकाएगा। अब हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां हर दिन नई अनिश्चितता लेकर आ रहा है। एक तरफ बातचीत के संकेत दिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमले भी जारी हैं। ट्रंप द्वारा दी गई समयसीमा और ईरान की शर्तों के बीच कोई स्पष्ट रास्ता नजर नहीं आ रहा। यह स्थिति न पूरी तरह युद्ध की है और न ही शांति की, बल्कि एक ऐसे गतिरोध की है जिसमें दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। एक महीने के इस संघर्ष ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक युद्ध केवल सैन्य ताकत का खेल नहीं रह गया है। यहां भूगोल, अर्थव्यवस्था, रणनीति और मनोबल सभी मिलकर परिणाम तय करते हैं। ईरान ने अपने नुकसान के बावजूद इन सभी मोर्चों पर खुद को बनाए रखा है, और यही वजह है कि वह आज भी इस युद्ध में खड़ा है। आने वाले दिनों में यह संघर्ष किस दिशा में जाएगा, यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि इस जंग ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि किसी देश को हराना केवल उसके नेताओं या ठिकानों को खत्म करने से संभव नहीं होता, जब तक उसकी रणनीति और आत्मविश्वास जिंदा है।

'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' का अगला वार तय, ट्रंप का दावा—ईरान में 3,554 टारगेट अभी बाकी, समझौते से पहले भी जारी रहेंगे हमले

फ्लोरिडा से एक बार फिर दुनिया को चौंकाने वाला संदेश देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ चल रहा सैन्य अभियान थमने वाला नहीं है, बल्कि अब इसका अगला और संभवतः अधिक आक्रामक चरण शुरू होने की तैयारी में है। 'फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव' शिखर सम्मेलन के मंच से ट्रंप ने जिस आत्मविश्वास और आक्रामकता के साथ 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' का जिक्र किया, उसने यह संकेत दे दिया है कि भले ही कूटनीतिक बातचीत की बातें सामने आ रही हों, लेकिन जमीन पर युद्ध की गति धीमी होने के कोई संकेत फिलहाल नहीं हैं। ट्रंप ने अपने संबोधन में खुलासा किया कि अमेरिकी सेना अब तक ईरान के 7,000 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मिशन अधूरा है। उनके अनुसार, अभी भी 3,554 ऐसे महत्वपूर्ण टारगेट बचे हुए हैं, जिनमें मिसाइल यूनिट, ड्रोन कंट्रोल सेंटर और रणनीतिक सैन्य ठिकाने शामिल हैं, जो अमेरिकी रडार पर हैं और जिन्हें "बहुत जल्द खत्म" कर दिया जाएगा। इस बयान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका इस अभियान को केवल दबाव बनाने के लिए नहीं, बल्कि निर्णायक बढ़त हासिल करने के इरादे से चला रहा है।

दिलचस्प बात यह रही कि ट्रंप ने पूरे घटनाक्रम को 'युद्ध' कहने से बचते हुए इसे 'सैन्य ऑपरेशन' बताया। यह केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति मानी जा रही है, जिससे अंतरराष्ट्रीय कानून और घरेलू राजनीतिक दबावों से बचा जा सके। 'युद्ध' शब्द के इस्तेमाल से जहां संसद और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जवाबदेही बढ़ जाती है, वहीं 'ऑपरेशन' कहकर इसे सीमित और नियंत्रित कार्रवाई के रूप में पेश किया जा सकता है। अपने भाषण में ट्रंप ने उस घटना का भी जिक्र किया जिसने इस संघर्ष को और अधिक संवेदनशील बना दिया था। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाते हुए एक साथ 101 मिसाइलें दागी थीं। यह हमला अगर सफल होता, तो यह इस युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता था। लेकिन ट्रंप के अनुसार, अमेरिका की उन्नत 'पैट्रियट' और अन्य रक्षा प्रणालियों ने इन सभी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। समुद्र में गिरे मलबे का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे अमेरिकी सैन्य क्षमता का बड़ा उदाहरण बताया और कहा कि "दुनिया ने देख लिया कि हमारी रक्षा प्रणाली कितनी मजबूत है।"

ट्रंप का सबसे विवादित और ध्यान खींचने वाला बयान तब आया, जब उन्होंने कहा कि "47 सालों से क्षेत्र में धौंस जमाने वाला ईरान अब खुद भाग रहा है।" उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी हमलों, खासकर B-2 बॉम्बर्स के इस्तेमाल ने ईरान की वायु रक्षा प्रणाली को बुरी तरह कमजोर कर दिया है। उनके मुताबिक अब अमेरिकी लड़ाकू विमान बिना किसी बड़े खतरे के ईरानी हवाई क्षेत्र में उड़ान भर पा रहे हैं, जो इस अभियान की सफलता को दर्शाता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरानी नेतृत्व अब "मिन्नतें" कर रहा है और समझौते के लिए तैयार है, हालांकि जमीन पर जारी हमले और ईरान की तरफ से मिल रहे जवाबी संकेत इस दावे की पूरी तरह पुष्टि नहीं करते। दरअसल, इस पूरे बयान के पीछे केवल सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी छिपा है। अमेरिका के भीतर बढ़ती महंगाई, तेल की कीमतों में उछाल और शेयर बाजार में अस्थिरता ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। ऐसे में ट्रंप एक तरफ अपनी ताकत दिखाकर घरेलू समर्थन बनाए रखना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ बातचीत के लिए भी दरवाजा खुला रखना चाहते हैं। यही कारण है कि उनके बयान में एक साथ आक्रामकता और समझौते के संकेत दोनों नजर आते हैं।

विशेषज्ञ मानते हैं कि 3,554 बचे हुए टारगेट का जिक्र केवल सैन्य जानकारी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संकेत है। यह ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश भी हो सकती है, जिससे उसे बातचीत की टेबल पर झुकने के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन इसके साथ ही यह जोखिम भी जुड़ा हुआ है कि अगर इन टारगेट्स पर हमले शुरू होते हैं, तो युद्ध और अधिक व्यापक और विनाशकारी रूप ले सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिन इस संघर्ष के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य बढ़त को और मजबूत करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ ईरान भी अब तक झुकने के संकेत नहीं दे रहा। ऐसे में 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' का अगला चरण केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला मोड़ बन सकता है।

मां की सुरक्षा, देश की प्रगतिः भारत ने मातृ मृत्यु दर में रचा ऐतिहासिक कीर्तिमान

नई दिल्ली। भारत ने मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जिसे न केवल राष्ट्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सराहा जा रहा है। प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित एक व्यापक वैश्विक विश्लेषण के अनुसार, वर्ष 1990 से 2023 के बीच भारत में मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) में लगभग 80 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। यह उपलब्धि भारत के स्वास्थ्य ढांचे, सरकारी नीतियों और जागरूकता अभियानों की सफलता का प्रतीक बनकर उभरी है।

आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1990 में भारत में प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर 508 महिलाओं की मृत्यु होती थी, जो 2023 तक घटकर 116 रह गई है। यही नहीं, नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) के 2021-23 के ताजा आंकड़े बताते हैं कि यह संख्या और गिरकर 88 प्रति लाख तक पहुंच चुकी है। यह प्रगति दर्शाती है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के तहत 2030 तक निर्धारित लक्ष्य—70 से नीचे MMR लाने—की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह उपलब्धि केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे लाखों महिलाओं के जीवन की रक्षा की कहानी छिपी है। सुरक्षित प्रसव, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता और जागरूकता अभियानों ने मिलकर इस बदलाव को संभव बनाया है।

वैश्विक तुलना में भी भारत की स्थिति काफी मजबूत होती दिख रही है। 2023 में भारत में कुल 24,700 मातृ मृत्यु

वायरल तस्वीर

दर्ज की गईं, जबकि पाकिस्तान में 10,300, इथियोपिया में 11,900 और नाइजीरिया में 32,900 मौतें हुईं। यह तुलना बताती है कि भारत ने सीमित संसाधनों के बावजूद मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस सफलता के पीछे कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का योगदान रहा है। जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने महिलाओं को अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और आशा कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका ने भी मातृ मृत्यु दर को कम करने में अहम योगदान दिया है।

वैश्विक स्तर पर स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के शोधकर्ताओं के अनुसार, वर्ष 2023 में दुनिया भर में लगभग 2.4 लाख मातृ मृत्यु दर्ज की गईं। हालांकि पिछले तीन दशकों में इसमें एक-तिहाई की कमी आई है, लेकिन अब भी कई देश इस लक्ष्य से काफी पीछे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव और उच्च रक्तचाप मातृ मृत्यु के प्रमुख कारण बने हुए हैं।

भारत के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक ऐसे समय में हासिल हुई है, जब दुनिया कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रही थी। महामारी के शुरुआती दौर में, खासकर 2020-21 के दौरान, मातृ मृत्यु दर में अस्थायी वृद्धि देखी गई थी। स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव और संक्रमण के खतरे ने गर्भवती महिलाओं के लिए चुनौतियां बढ़ा दी थीं। लेकिन टीकाकरण अभियान और स्वास्थ्य सेवाओं के पुनर्गठन के बाद स्थिति में तेजी से सुधार हुआ। इस पूरे परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच जितनी आसान और सुलभ होगी, मातृ मृत्यु दर उतनी ही तेजी से घटेगी। प्रसव पूर्व जांच, पोषण, समय पर चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सेवाएं—ये सभी कारक मिलकर माताओं के जीवन की रक्षा करते हैं।

सरकार और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में। वहां स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, जागरूकता और पोषण की स्थिति को और बेहतर बनाने की जरूरत है। इसके अलावा, किशोरियों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी जरूरी है, ताकि गर्भावस्था के दौरान जोखिम कम किया जा सके।

भारत की यह उपलब्धि यह भी दर्शाती है कि सही नीतियों, मजबूत इच्छाशक्ति और समाज की भागीदारी से बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। यह केवल एक सांख्यिकीय सुधार नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन है, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों को प्राथमिकता दी गई है।

आने वाले वर्षों में यदि इसी गति से प्रयास जारी रहे, तो भारत न केवल 2030 के लक्ष्य को समय से पहले हासिल कर सकता है, बल्कि अन्य विकासशील देशों के लिए एक आदर्श मॉडल भी बन सकता है।

अंततः, यह उपलब्धि हर उस मां के जीवन से जुड़ी है, जो सुरक्षित प्रसव के बाद अपने परिवार के साथ एक नई शुरुआत करती है। यही किसी भी समाज की असली प्रगति का पैमाना होता है—जब उसकी माताएं सुरक्षित हों, स्वस्थ हों और सम्मान के साथ जीवन जी सकें।

दुष्कर्म पीड़िता की पहचान पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त पहरा, सभी हाईकोर्ट को चेतावनी—कानून का उल्लंघन अब बर्दाश्त नहीं

नई दिल्ली से एक बेहद महत्वपूर्ण और सख्त संदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दुष्कर्म मामलों में पीड़िता की पहचान उजागर करना किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है और इस पर अब कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। शीर्ष अदालत ने देश के सभी हाईकोर्ट को कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी न्यायिक आदेश, फैसले या दस्तावेज में पीड़िता या उसके परिवार की पहचान किसी भी रूप में सामने न आए। अदालत ने इस तरह की लापरवाही को न केवल कानून का उल्लंघन माना, बल्कि इसे पीड़िता के सम्मान और गरिमा पर सीधा आघात बताया। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि वर्ष 2018 के ऐतिहासिक फैसले 'निपुण सक्सेना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' में पहले ही यह तय कर दिया गया था कि किसी भी माध्यम—चाहे वह प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हो या सोशल मीडिया—में दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जा सकती। इसके बावजूद, अदालत ने गंभीर चिंता जताई कि निचली अदालतों और कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों में भी इस दिशा-निर्देश का पालन सही तरीके से नहीं हो रहा है। अदालत ने इस स्थिति के लिए केवल कानूनी लापरवाही को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि समाज में मौजूद उस मानसिकता की ओर भी इशारा किया, जहां ऐसे मामलों को लेकर अब भी संवेदनशीलता और जागरूकता की कमी है। पीठ ने कहा कि दुष्कर्म जैसे अपराध केवल शारीरिक हिंसा नहीं होते, बल्कि यह पीड़िता के आत्मसम्मान, मानसिक स्थिति और सामाजिक अस्तित्व पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ऐसे में यदि उसकी पहचान सार्वजनिक होती है, तो यह उसे दोबारा पीड़ित करने जैसा है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भारतीय दंड संहिता की धारा 228A का विशेष रूप से उल्लेख किया, जिसे 1983 में इस उद्देश्य से जोड़ा गया था कि दुष्कर्म पीड़िताओं की पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखा जा सके। अदालत ने कहा कि इस प्रावधान का मकसद पीड़िताओं को सामाजिक बहिष्कार, शर्मिंदगी और मानसिक आघात से बचाना है। इससे पहले कानून में इस तरह की स्पष्ट सुरक्षा नहीं थी, जिसके कारण कई मामलों में पीड़िताओं को समाज में अपमान और अलगाव का सामना करना पड़ता था। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अब इस नियम के उल्लंघन को हल्के में नहीं लिया जाएगा। अदालत ने अपने आदेश की प्रति देश के सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने का निर्देश दिया है, ताकि हर स्तर पर इस कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके। यह निर्देश इस बात का संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को अब सहन नहीं करेगा। यह टिप्पणी उस समय आई जब सुप्रीम कोर्ट हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले की समीक्षा कर रहा था, जिसमें नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को बरी कर दिया गया था।

संपादकीय

किशोरों के हित में ऐतिहासिक फैसला

अमेरिका में लॉस एंजेलिस की एक जूरी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के घातक प्रभावों से त्रस्त एक युवती के पक्ष में सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले से दुनिया भर के अभिवावकों को राहत मिली है। दरअसल, सोशल मीडिया की लत लगाने से जुड़े एक मामले में मेटा और यूट्यूब पर 56 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि एक युवती ने मेटा और यूट्यूब पर आरोप लगाया था कि इनकी वजह से उसे सोशल मीडिया की घातक लत लगी। हालांकि, अब तक ये कंपनियां दलील देती रही हैं कि वे मात्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं और इसकी सामग्री के लिये जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन कोर्ट में वकीलों ने पीड़िता के पक्ष में दलील दी कि जानबूझकर इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं ताकि उपयोगकर्ता कथित सोशल मीडिया की लत के शिकार बन जाएं। शुरुआत से पहचान गुप्त रखने वाली बीस वर्षीय युवती केली के वकीलों की दलील को जूरी ने स्वीकार किया कि इस लत से उसकी मानसिक सेहत को नुकसान हुआ है। जूरी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों की दलीलों को दरकिनार करते हुए मेटा और यूट्यूब पर साठ लाख अमेरिकी डॉलर यानी छप्पन करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया है। जूरी ने माना कि गूगल तथा मेटा ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के संचालन में अपने मुनाफे के मद्देनजर अनुचित उपायों का सहारा लिया है। जूरी ने इसे अनैतिक भी बताया। जूरी के निर्णय के अनुसार इस मामले में जुर्माने की सत्तर फीसदी राशि मेटा तथा तीस फीसदी रकम गूगल को चुकानी होगी। उल्लेखनीय है कि पूरी दुनिया में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विरुद्ध हजारों मुकदमें चल रहे हैं। जिसमें कई वे लोग भी शामिल हैं जिनके बच्चों ने सोशल मीडिया की लत का शिकार होकर आत्मघाती कदम उठाये हैं। ब्रिटेन समेत कई देशों में अभिभावक इस लत से बच्चों को बचाने के लिये आंदोलन करते रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका में ही विभिन्न अदालतों में सोशल मीडिया के घातक प्रभावों से बच्चों को बचाने के लिये सैकड़ों मामले चल रहे हैं।

विश्वास किया जा रहा है कि इस मुकदमे के फैसले का प्रभाव उन तमाम मामलों में भी पड़ सकता है, जो दुनिया के विभिन्न देशों में चल रहे हैं। हालांकि, दोषी पाये गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कर्ताधर्ता इस फैसले से असहमति जताते हुए इसके खिलाफ अपील करने की बात कर रहे हैं। उनकी दलील है कि किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले घातक प्रभाव के अनेक अन्य कारण हो सकते हैं, जिसके लिये सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यूट्यूब के अधिकारियों का कहना है कि ये सोशल मीडिया साइट नहीं, सिर्फ वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। जबकि पीड़ित युवती के वकीलों की दलील थी कि मेटा आदि कंपनियों ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की संरचना ऐसी बनायी है कि किशोरों को इसकी आदत लग जाए। हकीकत ये है कि भारत समेत दुनिया के करोड़ों किशोर इसकी लत के शिकार बन रहे हैं। यही वजह है हफ्तों चले मुकदमे के दौरान बड़ी संख्या में किशोरों के अभिभावक वादी के पक्ष में अदालत के परिसर में मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि इस फैसले से पहले न्यू मेक्सिको में एक जूरी ने मेटा को इस बात के लिये जवाबदेह ठहराया कि उसके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध वयस्कों की सामग्री तक बच्चों की पहुंच बनी है, जिससे उनके जीवन में यौन अपराधियों का खतरा बढ़ गया है।, भारत समेत कई विकसित व विकासशील देशों में सोशल मीडिया से बच्चों के जीवन में पड़ने वाले घातक प्रभावों को लेकर चिंता सालों से बनी हुई है। लेकिन देश में इस बाबत कोई नियामक कानून न होने से कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आती। बच्चों की पढ़ाई खराब होने और उनके मानसिक रोगों से ग्रस्त होने की आशंका से अब अभिभावक आक्रोश व्यक्त करने लगे हैं। यही वजह है कि दुनिया के विकसित देशों में इन सोशल मीडिया प्लेटफार्म से बच्चों को दूर रखने के लिए कानून बन रहे हैं। आस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस और अब अन्य यूरोपीय देश भी इस दिशा में पहल कर रहे हैं ताकि एक निर्धारित आयु से ऊपर के बच्चे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच बना सकें।

यूएस शांति प्लान को ईरान द्वारा ठुकराए जाने के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक निहितार्थ क्या हैं?

"अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विशेषज्ञ बताते हैं कि ईरान द्वारा यूएस शांति योजना अस्वीकृति से मध्य पूर्व युद्ध अनिश्चितकाल तक लंबा खिंच सकता है, क्योंकि कोई नया समझौता होता नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं, जिस तरह से पहले यूक्रेन के पीछे पूरा यूरोप/अमेरिका खड़े थे, अब ईरान के पीछे रूस/चीन जैसे कद्दावर देश खड़े हो चुके हैं।

यदि आप देश-दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने के बजाए लाभप्रद और वर्चस्वमय हिंसा-प्रतिहिंसा को बढ़ावा देने की सीख सिखाने के आदी हो चुके हैं, तो सावधान हो जाइए। यह आपकी अप्राकृतिक हरकत है जिसकी कीमत आपको कभी न कभी चुकानी ही पड़ेगी। यह अकाट्य सत्य है क्योंकि देर-सबेर हुतात्माओं/निरीह पशु-प्राणियों के आत्मा के चक्रव्यूह (जबरदस्त गोलबंदी) में आप घिरेंगे और फिर आपके साथ भी वही होगा, जिसके सबक बेदर्द इतिहास के पन्नों में भरे पड़े हैं। जो बोइयेगा, वही काटियेगा, यह प्रकृति का अपरिवर्तित नियम है। सनातन धर्म में अकाल मृत्यु का स्रोत ऐसे ही प्रारब्ध जनित कर्मों का प्रतिफल है। आतंक उत्पादक और निर्यातक अमेरिका-ईरान इसी अकाट्य नैसर्गिक नियम के शिकार होते प्रतीत हो रहे हैं, फिर भी उन्हें सद्बुद्धि नहीं आई है, जबकि इजरायल तो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जूझ रहा है। वह धर्मयुद्ध का शिकार है। वह अल्पसंख्यक यहुदी होने की कीमत चुका रहा है। वहीं, शांतिप्रिय और गुटनिरपेक्ष देश भारत चाहकर भी वसुधैव कुटुम्बकम की भावना सबके दिलोदिमाग में नहीं जगा पा रहा है। उसके सर्वे भवंतु सुखिनः वाली सोच की धज्जियां पाकिस्तान उड़ा-उड़वा रहा है।

इसलिए सबको ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। चाहे रूस-यूक्रेन युद्ध हो या भारत-पाकिस्तान युद्ध या फिर संभावित चीन-ताइवान युद्ध, या फिर अन्य द्विदेशीय सीमा संघर्ष, सबको टालना, टलवाना जरूरी है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को कठोर होना पड़ेगा। वीटो पावर प्राप्त पांचों देशों को और अधिक जिम्मेदार बनना पड़ेगा। हथियारों और दवाओं को कारोबार नहीं, बल्कि सुरक्षा और

सेवा के नजरिये से देखना पड़ेगा।

ऐसा इसलिए कि पूरी दुनिया में इस्लामिक शासन लाने के स्वप्नद्रष्टा देश ईरान द्वारा पूंजीवादी लोकतांत्रिक मुल्क अमेरिका के 15 सूत्री अमेरिकी शांति योजना को ठुकरा दिया है। इससे मध्य पूर्व में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो क्षेत्रीय और वैश्विक कूटनीति को प्रभावित कर रहा है। इससे युद्ध का अभूतपूर्व विस्तार और द्विपक्षीय बर्बादी तय है। कूटनीतिक मामलों के जानकारों के मुताबिक, जहां ईरान ने अमेरिकी 15-सूत्री योजना (जिसमें परमाणु सुविधाओं का विघटन और मिसाइल सीमाएं शामिल हैं) को "अत्यधिक" बताकर खारिज कर दिया, वहीं ईरान ने अमेरिकी-इजरायल गुटबंदी के ऊपर अपनी पांच महत्वपूर्ण शर्तें रखीं हैं, जैसे युद्ध क्षतिपूर्ति, होर्मुज जलडमरूमध्य पर संप्रभुता और हमलों का अंत आदि। इससे संघर्ष लंबा खिंच सकता है, क्योंकि ईरान हमले जारी रखे हुए है।

इस पूरे प्रकरण में कठोर क्षेत्रीय प्रतिक्रियाएं मिली हैं। जहां अरब-खाड़ी देशों, यथा- सऊदी, यूएई आदि और जॉर्डन ने ईरान की कार्रवाइयों की निंदा की, वहीं परस्पर एकजूट होकर ईरान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं पर विराम लगाने के उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता भी जताई। साथ ही, यूएनएससी में प्रस्ताव लाया गया। जबकि अमेरिकी एजेन्ट पाकिस्तान बनावटी मध्यस्थ बना रहा है, लेकिन सबके बीच पारस्परिक अविश्वास गहरा गया है।

जहां तक वैश्विक प्रभाव की बात है तो संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि होर्मुज बंद होने से तेल (20% वैश्विक आपूर्ति) कारोबार प्रभावित हो रहा है, जिससे कीमतें $100+ पहुंचीं और अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। इससे प्रभावित यूरोप, भारत, पूर्वी एशियाई देश और अन्य ने शांति की मांग की, जबकि अपना शांति प्रस्ताव खारिज होते ही अमेरिका ने और अधिक सैनिक ईरान की ओर भेज दिए हैं। इससे कूटनीतिक चुनौतियां भी उपजी हैं। जहां यह अस्वीकृति ट्रंप प्रशासन की पहल को झटका देती है, वहीं ईरान को मजबूत बनाती है और मध्यस्थों (पाकिस्तान, मिस्र) की भूमिका कमजोर करती है। इससे भविष्य में सैन्य एस्केलेशन या नए मध्यस्थ (रूस?) का उभार संभव है।

अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विशेषज्ञ बताते हैं कि ईरान द्वारा यूएस शांति योजना अस्वीकृति से मध्य पूर्व युद्ध अनिश्चितकाल तक लंबा खिंच सकता है, क्योंकि कोई नया समझौता होता नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं, जिस तरह से पहले यूक्रेन के पीछे पूरा यूरोप/अमेरिका खड़े थे, अब ईरान के पीछे रूस/चीन जैसे कद्दावर देश खड़े हो चुके हैं। इससे इस युद्ध में युद्धोन्मादी देश अमेरिका की मिट्टी पलीद हो रही है। यूरोप का नाटो भी पूरी तरह से अमेरिका के पक्ष में खड़ा नहीं है, बल्कि अपना हाथ खींच चुका है। इससे ईरान के हौसले बुलंद हैं।

विशेषज्ञों के इस युद्ध से जुड़े अनुमान पहले 4-6 सप्ताह के थे, लेकिन अब महीनों या उससे अधिक का खतरा बता रहे हैं। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने युद्ध को 4-5 सप्ताह का बताया था, जबकि पेंटागन ने 4-6 सप्ताह का अनुमान लगाया। लेकिन 26 दिनों बाद भी हमले जारी हैं, ईरान ने भी जबर्दस्त काउंटर किया है। उसने युद्ध रोकने सम्बन्धी एक काउंटर-प्रस्ताव भी रखा हुआ है। वर्तमान स्थिति यह है कि ईरान ने 15-सूत्री योजना को "अनुचित" ठहराया, और अपनी शर्तें (क्षतिपूर्ति, होर्मुज नियंत्रण) रखीं। वहीं, अमेरिका 50,000+ सैनिक भेज चुका है, जिससे और संघर्ष तीव्र होता जा रहा है।

विशेषज्ञ भविष्यवाणियां दिलचस्प हैं। पूर्व सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि न्यूनतम 4-5 सप्ताह लेकिन "महीनों" लग सकते हैं। कुछ विश्लेषक ईरान की हार मानते हैं लेकिन अवधि लंबी होने पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। इसका कोई निश्चित अंत नहीं है, क्योंकि मध्यस्थ असफल दिखाई दे रहे हैं। भले ही ईरान के साथ युद्ध में करीब चार हफ्तों बाद अमेरिका ने समझौते की इच्छा जताई है, जो पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है, लेकिन शांति की खातिर दोनों पक्षों को अपनी अपनी जिद छोड़नी होगी। अन्यथा पूरी दुनिया की आर्थिक बर्बादी तय है।

वैसे तो, अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिये ईरान तक 15 सूत्रीय युद्धविराम प्रस्ताव भेजा है। इसमें तेहरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद करने और होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलने जैसी मांगें शामिल हैं। जबकि कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने भी अपनी मांगें रखी है, जिसमें सबसे अहम यह है कि अमेरिका को पश्चिम एशिया में अपने सभी सैन्य ठिकाने बंद करने होंगे। वहीं, पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मुकद्दम ने वॉशिंगटन और तेहरान के बीच किसी तरह की बातचीत से इनकार किया है। उधर, ईरान के एक सैन्य प्रवक्ता ने भी ट्रंप के प्रस्ताव का मजाक उड़ाया। लेकिन, अहम यह है कि अब कम से कम शांति की चर्चा तो हो रही है। ईरान और अमेरिका एक-दूसरे से जो चाहते है, वह मुश्किल है। कमोबेश इन्ही मामलों पर फरवरी में भी बातचीत अटकी थी। इन बिंदुओं को वह रेड लाइन कह सकते है, जिसे पार करना दोनों देशों के लिए असंभव है। लेकिन, आमतौर पर युद्ध के बीच बातचीत इसी तरह से शुरू होती है। इसलिए यकायक यह उम्मीद नहीं कर सकते कि दोनों देश सीधे आमने-सामने बैठ जाएंगे और उनकी बात बन जाएगी। बल्कि दोनों को कॉमन ग्राउंड तलाशना होगा। तभी शांति की राह तैयार होगी।

चूंकि अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे की कमी उन्हें सीधी बातचीत शुरू करने से रोक रही है। इससे पहले हुई सारे वार्ताएं नाकाम रही है और उनके दरम्यान ही अमेरिका-इस्राइल ने हमले शुरू कर दिए। ऐसे में तेहरान की हिचक समझी जा सकती है। लिहाजा, बातचीत पर आगे बढ़ने के लिए यह भी जरूरी है कि पहले ईरान पर हमले बंद किए जाएं। यह नहीं हो सकता कि ट्रंप संघर्षविराम का प्रस्ताव भेजें और साथ में पश्चिम एशिया में अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ाते जाएं। अब तक के संघर्ष ने इतना तो बता दिया कि ताकत के जोर से सिर्फ तबाही ही मिलेगी। ट्रंप को इस्राइल को भी हमले रोकने के लिए मनाना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी पक्ष समझौते का पालन नहीं करता है. तो शांति को कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कुलमिलाकर स्थिति जटिल है, और राहें मुश्किल, इसलिए चेत जाने में ही सबकी भलाई निहित है।

प्रेरणा

हर इंसान का सम्मानः महानता की असली पहचान

भारत के पूर्व राष्ट्रपति ए. पी. जे. अब्दुल कलाम का जीवन जितना विज्ञान और उपलब्धियों के लिए जाना जाता है, उतना ही उनकी सादगी, विनम्रता और मानवीय दृष्टिकोण के लिए भी प्रेरणादायक है। वे केवल एक महान वैज्ञानिक या राष्ट्राध्यक्ष नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने व्यवहार से यह साबित किया कि सच्ची महानता दूसरों को सम्मान देने में छिपी होती है।

एक बार की बात है, जब वे देश के राष्ट्रपति थे और उन्हें एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम भव्य था, मंच सुसज्जित था और वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में उत्साह था। जैसे ही डॉ. कलाम मंच पर पहुंचे, पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उन्होंने अपने सरल लेकिन प्रेरणादायक शब्दों से उपस्थित लोगों को संबोधित किया और अपने विचारों से सभी को नई ऊर्जा से भर दिया।

कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, जब अधिकांश लोग वहां से जाने लगे, तब एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने उस दिन की असली सीख को जन्म दिया। डॉ. कलाम मंच से नीचे उतरे और धीरे-धीरे बाहर की ओर बढ़ने लगे। तभी उनकी नजर एक साधारण कर्मचारी पर पड़ी, जो चुपचाप कुर्सियां समेट रहा था। वह बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी प्रशंसा की चाह के अपना काम पूरी लगन से कर रहा था।

जहां अधिकांश लोग ऐसे दृश्य को नजरअंदाज कर देते हैं, वहीं डॉ. कलाम की नजरों में हर व्यक्ति का महत्व था। वे सीधे उस कर्मचारी के पास गए, मुस्कुराए और बड़े ही स्नेह से बोले, "आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी व्यवस्था संभाली।" यह सुनकर वह कर्मचारी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि देश का राष्ट्रपति उससे इस तरह बात कर रहा है।

उस कर्मचारी की आंखों में एक अलग ही चमक थी। यह केवल खुशी की चमक नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान और गर्व की भावना से भरी हुई थी। उसने शायद पहली बार महसूस किया कि उसका काम भी महत्वपूर्ण है, कि उसकी मेहनत की भी कद्र है। उस एक वाक्य ने उसके भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास भर दिया।

इस पूरे दृश्य को वहां मौजूद कई लोगों ने देखा और वे भी गहराई से प्रभावित हुए। उन्हें यह समझ में आया कि महानता केवल बड़े पद या ऊंचे ओहदे में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। डॉ. कलाम ने इसके बाद उपस्थित लोगों से कहा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम समाज के लिए आवश्यक होता है और हर व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है।

समाज में अक्सर यह देखा जाता है कि लोग किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके काम या पद के आधार पर करते हैं। जो लोग उच्च पदों पर होते हैं, उन्हें अधिक सम्मान मिलता है, जबकि साधारण काम करने वाले लोगों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन यह सोच गलत है। अगर हम गहराई से सोचें, तो पाएंगे कि हर व्यक्ति अपनी भूमिका में उतना ही महत्वपूर्ण है।

एक कार्यालय में काम करने वाला कर्मचारी, एक सफाईकर्मी, एक चालक या एक तकनीशियन—सभी मिलकर ही किसी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। यदि इनमें से कोई एक भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से न निभाए, तो पूरी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसलिए हर काम का अपना महत्व है और हर व्यक्ति सम्मान का पात्र है।

डॉ. कलाम की यह सोच केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके व्यवहार में स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। वे जहां भी जाते, लोगों से बड़े ही आत्मीयता से मिलते, उनकी बातों को ध्यान से सुनते और हर व्यक्ति को महत्व देते। यही कारण था कि वे केवल एक नेता नहीं, बल्कि लोगों के दिलों के नेता बन गए।

इस घटना से हमें यह भी सीख मिलती है कि सम्मान देना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए न तो पैसे की जरूरत होती है और न ही किसी विशेष संसाधन की। केवल एक सच्ची भावना और थोड़ी सी संवेदनशीलता ही पर्याप्त होती है। एक छोटी सी प्रशंसा, एक धन्यवाद या एक मुस्कान किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है।

उस कर्मचारी के जीवन में भी यही हुआ। उस दिन के बाद उसने अपने काम को और अधिक मेहनत और समर्पण के साथ करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब उसे यह महसूस हो गया था कि उसका काम केवल एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा योगदान है जिसकी कद्र की जाती है। यह भावना किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है।

यह कहानी हमें आत्ममंथन करने के लिए भी प्रेरित करती है। हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या हम अपने आसपास के लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, जैसा हमें करना चाहिए। क्या हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं जो हमारे जीवन को आसान बनाते हैं? क्या हम हर व्यक्ति के काम का सम्मान करते हैं? अक्सर हम अपनी व्यस्तता में इन छोटी-छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम केवल अपने काम और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दूसरों के योगदान को भूल जाते हैं। लेकिन यदि हम सच में एक बेहतर समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाना होगा।

हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है और अपने कर्तव्यों को निभा रहा है। इसलिए हमें हर किसी के प्रति सम्मान और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। यही एक सच्चे और संवेदनशील समाज की पहचान होती है।

डॉ. कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची महानता विनम्रता में होती है। उन्होंने कभी अपने पद या शक्ति का अहंकार नहीं किया, बल्कि हमेशा एक सामान्य इंसान की तरह जीवन जिया। उनका यही गुण उन्हें दूसरों से अलग और विशेष बनाता है।

अंततः, यह घटना हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है—सम्मान देना सीखिए। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं, तो हम न केवल उनके आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं, बल्कि अपने समाज को भी बेहतर बनाते हैं। एक छोटा सा सम्मान किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यदि हम सभी इस छोटी सी सीख को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा समाज न केवल अधिक मजबूत होगा, बल्कि अधिक मानवीय और संवेदनशील भी बनेगा। और यही वह असली परिवर्तन है, जिसकी आज के समय में सबसे अधिक आवश्यकता है।

जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता: बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणाम और पारंपरिक भ्रांतियाँ

भारत आज दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। 2024 में भारत की जनसंख्या लगभग 145 करोड़ को पार कर गई है। यह एक ऐसी समस्या है जो देश के विकास, संसाधनों, पर्यावरण और लोगों के जीवन स्तर पर सीधा असर डालती है। एक तरफ जहाँ देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ती आबादी उस तरक्की को खा जा रही है। सड़कों पर भीड़, अस्पतालों में लंबी कतारें, स्कूलों में जगह की कमी और बेरोजगारी—ये सब बढ़ती जनसंख्या के प्रत्यक्ष परिणाम हैं। इस लेख में हम बढ़ती जनसंख्या से होने वाले नुकसानों को समझेंगे और उन पारंपरिक विचारधाराओं का खंडन करेंगे जो अधिक संतान पैदा करने को प्रेरित करती हैं। बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणामः गरीबी और भुखमरीः जब किसी परिवार में कमाने वाला एक होता है और खाने वाले दस, तो गरीबी अपने आप आ जाती है। यही बात पूरे देश पर लागू होती है। भारत में उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तेजी से आबादी बढ़ रही है। नतीजा यह होता है कि प्रति व्यक्ति आय कम रह जाती है। करोड़ों लोग आज भी दो वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे हैं। गरीबी का सीधा संबंध अधिक जनसंख्या से है।

बेरोजगारी : हर साल लाखों युवा पढ़-लिखकर नौकरी ढूँढने निकलते हैं, लेकिन नौकरियाँ उतनी तेजी से नहीं बढ़तीं जितनी तेजी से लोग बढ़ रहे हैं। एक सरकारी पद के लिए लाखों आवेदन आते हैं। इससे निराशा, अपराध और सामाजिक अस्थिरता बढ़ती है। अगर जनसंख्या नियंत्रित होती तो हर हाथ को काम मिलना आसान होता।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझः सरकारी स्कूलों में एक कक्षा में 60-70 बच्चे बैठते हैं, जहाँ शिक्षक का ध्यान हर बच्चे पर देना असंभव हो जाता है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की इतनी भीड़ होती है कि डॉक्टर को एक मरीज को देखने के लिए मुश्किल से दो मिनट मिलते हैं। बढ़ती आबादी के कारण सरकार चाहकर भी हर व्यक्ति तक अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुँचा पाती।

पर्यावरण का विनाशः ज्यादा लोग यानी ज्यादा जमीन की जरूरत, ज्यादा पानी की खपत, ज्यादा प्रदूषण और ज्यादा कचरा। जंगल काटकर बस्तियाँ बसाई जा रही हैं, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, भूजल का स्तर गिर रहा है। जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा कारण अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि है। अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाली पीढ़ियों को साफ पानी और स्वच्छ हवा भी नसीब नहीं होगी।

आवास और शहरीकरण की समस्याः शहरों में जगह कम पड़ रही है। मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में झुग्गी-झोपड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग तंग और अस्वच्छ जगहों पर रहने को मजबूर हैं। ट्रैफिक जाम, पानी की कमी और बिजली की समस्या — ये सब अधिक जनसंख्या का ही नतीजा है।

अपराध और सामाजिक अशांतः जब लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होतीं तो अपराध बढ़ता है। भूख, बेरोजगारी और निराशा लोगों को गलत रास्ते पर धकेलती है। अधिक जनसंख्या वाले इलाकों में चोरी, लूट और हिंसा की घटनाएँ ज्यादा देखी जाती हैं।

पारंपरिक भ्रांतियाँ और उनका खंडनः हमारे समाज में कई ऐसी पुरानी मान्यताएँ प्रचलित हैं जो लोगों को अधिक संतान पैदा करने के लिए प्रेरित करती हैं। इन मान्यताओं की जड़ें धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं में हैं। आइए इन भ्रांतियों को एक-एक करके समझें और उनका तर्कपूर्ण खंडन करें।

भ्रांति 1: संतान से मोक्ष मिलता हैः यह सबसे प्रचलित मान्यता है कि पुत्र के बिना मोक्ष नहीं मिलता। कहा जाता है कि पुत्र पिंडदान करेगा तो पूर्वज मुक्त होंगे। इस मान्यता के कारण लोग बेटे की चाह में कई संतानें पैदा करते रहते हैं।

खंडन : अगर हम धर्मग्रंथों को गहराई से पढ़ें तो मोक्ष कर्म, ज्ञान और भक्ति से मिलता है, संतान की संख्या से नहीं। भगवद्गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं कि मोक्ष का मार्ग निष्काम कर्म और आत्मज्ञान है। कोई भी धर्मग्रंथ यह नहीं कहता कि जिसके ज्यादा बच्चे होंगे, उसे ज्यादा पुण्य मिलेगा। मोक्ष व्यक्ति के अपने आचरण, सदाचार और आध्यात्मिक साधना पर निर्भर करता है। अगर संतान से ही मोक्ष मिलता तो संन्यासियों, साधुओं और ऋषि-मुनियों को मोक्ष कैसे प्राप्त होता? शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद — इन सबने संतान नहीं उत्पन्न की, फिर भी ये महापुरुष माने गए।

भ्रांति 2: बेटा जरूरी है, बेटी से काम नहीं चलता : समाज में यह धारणा गहरी जड़ें जमाए बैठी है कि बेटा वंश आगे बढ़ाता है, बुढ़ापे का सहारा बनता है और अंतिम संस्कार करता है। इसलिए लोग बेटे की चाह में बच्चे पैदा करते रहते हैं।

खंडन : आज के समय में बेटियाँ हर क्षेत्र में बेटों से आगे निकल रही हैं। चाहे सेना हो, अंतरिक्ष हो, खेल हो या प्रशासन — बेटियाँ हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं। कई बेटियाँ अपने माता-पिता की बुढ़ापे में बेटों से बेहतर देखभाल करती हैं। रही बात अंतिम संस्कार की, तो आज कानूनी रूप से बेटी को भी यह अधिकार प्राप्त है। जो लोग बेटे की चाह में पाँच-छह बेटियाँ पैदा कर देते हैं, वे न उन बेटियों को अच्छी शिक्षा दे पाते हैं, न अच्छा जीवन। यह कोई समझदारी नहीं, बल्कि मूर्खता है।

भ्रांति 3 : ज्यादा बच्चे यानी बुढ़ापे का सहारा : कई लोग सोचते हैं कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे, बुढ़ापे में उतना ज्यादा सहारा मिलेगा। उनका मानना है कि एक-दो बच्चे हुए तो कौन देखभाल करेगा।

खंडन : सच्चाई यह है कि आज के समय में ज्यादा बच्चे होने का मतलब ज्यादा सहारा नहीं, बल्कि ज्यादा खर्चा और ज्यादा चिंता है। अगर आप दो बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, उन्हें संस्कारवान बनाते हैं, तो वे दो बच्चे दस बच्चों से बेहतर देखभाल करेंगे। दूसरी तरफ, अगर पाँच-छह बच्चे हों और किसी को भी अच्छी शिक्षा या संस्कार न मिले, तो वे सब मिलकर भी बुढ़ापे में सहारा नहीं बन पाएँगे। आज वृद्धाश्रमों में ऐसे बहुत से बुजुर्ग हैं जिनके चार-पाँच बच्चे हैं, लेकिन कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं।

अभियान

मंगल दोष से मुक्ति का दिव्य मार्ग: उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर की भात पूजा का रहस्य

वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का प्रभाव मानव जीवन पर गहराई से माना गया है, और इनमें मंगल ग्रह एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंगल ग्रह को साहस, ऊर्जा, भूमि, रक्त, शक्ति और विवाह का कारक माना जाता है। जब यह ग्रह अनुकूल स्थिति में होता है, तो व्यक्ति को आत्मविश्वास, सफलता और नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है। लेकिन जब इसकी स्थिति कुंडली में प्रतिकूल हो जाती है, तब यही मंगल कई प्रकार की समस्याओं का कारण बन जाता है, जिसे सामान्य भाषा में "मंगल दोष" या "मांगलिक दोष" कहा जाता है।

मंगल दोष विशेष रूप से विवाह से जुड़ी परेशानियों के लिए जाना जाता है। ऐसे जातकों के विवाह में देरी, वैवाहिक जीवन में तनाव, क्रोध की अधिकता, आर्थिक समस्याएं और पारिवारिक कलह जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में इसके निवारण के लिए विशेष उपाय, पूजा और तीर्थ स्थलों का महत्व बताया गया है। इन्हीं में से एक प्रमुख स्थान है मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित मंगलनाथ मंदिर, जिसे मंगल दोष निवारण का सबसे शक्तिशाली केंद्र माना जाता है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह मंदिर मंगल देव का जन्मस्थान है। यह पवित्र स्थान शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जो अपने आप में अत्यंत आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि मंगल देव की उत्पत्ति भगवान शिव के पसीने की बूंद से हुई थी, जिससे उनका स्वभाव उग्र और तेजस्वी माना जाता है।

यही उग्रता जब जीवन में असंतुलन पैदा करती है, तब इसे शांत करने के लिए विशेष पूजा विधियों का सहारा लिया जाता है। मंगलनाथ मंदिर में होने वाली "भात पूजा" इसी दिशा में एक अत्यंत प्रभावी उपाय मानी जाती है। इस पूजा में चावल का विशेष महत्व होता है। चावल की प्रकृति शीतल मानी जाती है, और यह मंगल के उग्र प्रभाव को संतुलित करने में सहायक होता है। श्रद्धालु इस पूजा के माध्यम से मंगल देव को शांत करने और अपने जीवन से नकारात्मक प्रभावों को दूर करने का प्रयास करते हैं।

भात पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें श्रद्धा, विश्वास और ऊर्जा का अद्भुत संगम होता है। जब कोई व्यक्ति पूरी आस्था के साथ इस पूजा को करता है, तो उसके मन में सकारात्मकता बढ़ती है, और जीवन की बाधाएं धीरे-धीरे कम होने लगती हैं। कई श्रद्धालुओं का मानना है कि इस पूजा के बाद उनके विवाह संबंधी समस्याएं हल हुईं, कर्ज से राहत मिली और मानसिक शांति प्राप्त हुई। मंगलनाथ मंदिर की विशेषता केवल इसकी पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। उज्जैन प्राचीन काल से ही ज्योतिष और खगोल विज्ञान का प्रमुख केंद्र रहा है। यह वही स्थान है, जहां समय की गणना और ग्रह-नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता था। इसलिए यहां स्थित मंगलनाथ मंदिर को विशेष रूप से मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है।

इसके अलावा, महाराष्ट्र के अमलनेर में स्थित मंगल देव मंदिर भी भक्तों के लिए आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां मंगल देव की एक दुर्लभ प्रतिमा स्थापित है, जिसकी पूजा विशेष रूप से मंगलवार के दिन की जाती है। इस दिन यहां अभिषेक और शांति पाठ का आयोजन होता है, जिससे जीवन की बाधाएं दूर होने की मान्यता है।

मंगल दोष के निवारण के लिए केवल मंदिरों में पूजा ही नहीं, बल्कि कुछ सरल और प्रभावी उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अपना सकता है। सबसे प्रमुख उपाय है भगवान हनुमान की उपासना। हनुमान जी को मंगल का इष्ट देव माना जाता है। इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करने से मंगल के अशुभ प्रभाव कम होने लगते हैं। इसके साथ ही दान का भी विशेष महत्व होता है। मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल, तांबे के बर्तन, लाल वस्त्र और गुड़ का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दान मंगल ग्रह को प्रसन्न करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।

मंत्र जाप भी एक अत्यंत प्रभावी उपाय है। "ॐ भौमाय नमः" और "ॐ अंगारकाय नमः" मंत्रों का नियमित रूप से 108 बार जाप करने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन की परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त होने लगती हैं। यह मंत्र व्यक्ति के भीतर ऊर्जा संतुलन स्थापित करने में सहायक होते हैं। मंगल को "भूमि पुत्र" भी कहा जाता है, इसलिए मिट्टी से जुड़े उपाय भी विशेष फलदायी माने जाते हैं। मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करने से मंगल दोष शांत होता है और व्यक्ति को स्थिरता प्राप्त होती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है, जो जीवन में अस्थिरता और तनाव का सामना कर रहे हैं।

व्रत और संयम भी मंगल दोष निवारण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो लोग विवाह में बाधाओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें कम से कम 21 मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और शाम के समय हनुमान जी को फलाहार अर्पित करना चाहिए। यह अनुशासन व्यक्ति के भीतर आत्मसंयम और सकारात्मकता को बढ़ाता है।

आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो मंगल दोष केवल ग्रहों की स्थिति का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की ऊर्जा के असंतुलन को भी दर्शाता है। जब व्यक्ति क्रोध, अहंकार और असंयम से भर जाता है, तो यह मंगल के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा देता है। इसलिए केवल बाहरी उपाय ही नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि भी आवश्यक है।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्तित्व भी यह मानते थे कि जीवन में संतुलन, अनुशासन और सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। जब हम अपने भीतर के विचारों को शुद्ध करते हैं और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाते हैं, तब ग्रहों का प्रभाव भी स्वतः संतुलित होने लगता है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि मंगल दोष कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि हमें अपने जीवन में संतुलन लाने की आवश्यकता है। उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर और वहां की भात पूजा इस दिशा में एक शक्तिशाली माध्यम है, जो व्यक्ति को न केवल समस्याओं से मुक्ति दिलाता है, बल्कि उसे आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त बनाता है।

यदि श्रद्धा, विश्वास और सही उपायों के साथ प्रयास किया जाए, तो मंगल दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही इस पूरी परंपरा का सार है—आस्था, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाना।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राजकोट में 1010 आवासों सहित 751 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- 'ईज ऑफ लिविंग' की मंशा के साथ आगे बढ़ते राजकोट को 751.20 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की भेंट मिली
- राज्य सरकार योजनाबद्ध विकास कार्यों को तत्काल मंजूरी देती है
- विकास कार्यों के लिए गुजरात का वित्तीय प्रबंधन देश भर में प्रथम

.....

प्रभारी मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी

- राजकोट महानगर पालिका द्वारा गत 15 दिनों में 1100 करोड़ रुपए के कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास का रिकॉर्ड
- समान नागरिक संहिता विधेयक लाने वाला गुजरात देश का दूसरा राज्य

- भविष्य के राजकोट के लिए 543 करोड़ रुपए के 40 नए प्रोजेक्ट की नींव रखी गई
- सड़क, ड्रेनेज और रोशनी के कार्यों से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी नई गति
- लोगों की सुख-सुविधा के लिए राज्य सरकार सदैव तत्पर : शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार को राजकोट में महानगर पालिका के 751.20 करोड़ रुपए के 45 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 119.05 करोड़ रुपए के खर्च से नवनिर्मित ईडब्ल्यूएस-2 प्रकार के आवासों का लोकार्पण करके मुख्यमंत्री ने 1010 परिवारों को आधुनिक सुविधा युक्त 'अपने घर' की भेंट दी है। इसके साथ ही, 9.78 करोड़ रुपए के खर्च से निर्मित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) और नए व्हीकल टेस्ट ट्रैक का भी लोकार्पण किया गया।

राजकोट में प्रमुख स्वामी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि 'ईज ऑफ लिविंग' और 'अर्न वेल, लिव वेल' की मंशा के साथ आगे बढ़ रहे राजकोट को आज 751.20 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की भेंट मिली है। गुजरात राज्य का विकास मॉडल और विकास कार्यों के लिए गुजरात का वित्तीय प्रबंधन देश भर में अव्वल स्थान पर है।

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि नागरिकों के

कल्याण के लिए जरूरी एक भी विकास कार्य बाकी नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार योजनाबद्ध विकास कार्यों को कभी नामंजूर नहीं करती, बल्कि ऐसे कार्यों की योजना को तत्काल मंजूरी दी जाती है। इस अवसर पर उन्होंने निर्माणाधीन विकास कार्यों में गुणवत्ता को बनाए रखने पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को 2047 तक विकसित बनाने का संकल्प दिया है, तब 'विकसित भारत' के लिए देश के आम नागरिक को मुख्यधारा में शामिल करना आवश्यक है, और इसके लिए ही राज्य में 'वाइब्रेंट गुजरात समिट' को रीजनल यानी क्षेत्रीय स्तर पर ले जाया गया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बतौर सरकार के मुखिया अपने शासनकाल के 8931 दिन पूरे करने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि के तौर पर श्री नरेन्द्र मोदी की यात्रा की शुरुआत राजकोट से हुई थी और राजकोट से शुरू हुआ यह रिकॉर्ड आज लगातार आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी के कल्याण के मंत्र के साथ कार्यरत श्री नरेन्द्र मोदी गरीबों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाए हैं। आज पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए और डीजल में एक्साइज ड्यूटी को शून्य कर दिया गया है। जब कभी दुनिया में संकट पैदा हुआ है, तब श्री नरेन्द्र मोदी ने हिम्मतपूर्वक निर्णय लिए हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विजन है कि देश के प्रत्येक गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार के पास 'अपना घर' हो। गुजरात सरकार इस सपने को साकार करने के लिए दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ रही है। आज राजकोट में आवास योजना के जरिए एक हजार से अधिक परिवारों को उनके सपनों का घर मिल रहा है।

इस अवसर पर राजकोट जिला प्रभारी मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने आज के कार्यक्रम को जनकल्याण का ऐतिहासिक अवसर करार देते हुए कहा कि राजकोट महानगर पालिका द्वारा पिछले 15 दिनों में ही 1100 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जो एक रिकॉर्ड है।

हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा विधानसभा में पेश किए गए और बहुमत से पारित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक के संबंध में श्री वाघाणी ने कहा कि यूसीसी विधेयक मुख्यमंत्री का 'दिल' है। गुजरात समूचे देश में यह विधेयक लाने वाला दूसरा राज्य है। इसके साथ ही, उन्होंने यह आश्वासन दिया कि गुजरात सरकार जनता के हित के लिए जरूरी सभी निर्णय करती रहेगी।

उन्होंने कहा कि सौराष्ट्र से विकास की धारा गुजरात भर में प्रवाहित हो रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में अविरत विकास यात्रा के परिणामस्वरूप हुआ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। राजकोट महानगर पालिका के निरंतर प्रयासों के चलते आज राजकोट के हर कोने का विकास हुआ है। शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला ने कहा कि आज राजकोट में शहरी विकास विभाग के 543 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और 207 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ है। उन्होंने इसके लिए नागरिकों को बधाई दी।

श्रीमती वाघेला ने कहा कि उत्सवप्रिय और रंगीला राजकोट अब विकास कार्यों में भी आगे बढ़ रहा है। ड्रेनेज, पानी और सड़कों के विकास कार्यों से आगे बढ़कर राज्य सरकार ने गरीबों की वेदना को समझते हुए आवासों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार लोगों के कल्याण के लिए लगातार तत्पर रहेगी और आगामी दिनों में राजकोट विकास के मामले में मॉडल सिटी बनेगा। इस अवसर पर सांसद श्री परशोत्तमभाई रूपाला ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात का सर्वांगीण विकास हुआ है। हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वाइब्रेंट गुजरात समिट की ऐतिहासिक शुरुआत हुई थी। इसे आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दिशा-निर्देश में यह वाइब्रेंट समिट अब क्षेत्रीय स्तर पर पहुंच गई है। यह गर्व की बात है कि राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन हुआ और इसे सफलता मिली।

वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में गुजरात की ऐतिहासिक सफलता

- कच्छ में एक दशक बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) के चूजे का जन्म-आगमन : वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया
- 'ऑपरेशन एग ट्रांसफर' के अंतर्गत राजस्थान के ब्रीडिंग सेंटर से गोडावण के एक उर्वर अंडे को 19 घंटे की सड़क यात्रा के जरिए पोर्टेबल इनक्यूबेटर में सुरक्षित रूप से कच्छ लाया गया
- यह सफलता 'जम्पस्टार्ट एप्रोच' नामक नवाचारपूर्ण संरक्षण प्रयास के माध्यम से संभव हुई

गांधीनगर : गुजरात और राजस्थान के वन विभागों, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (डब्ल्यूआईआई) के संयुक्त प्रयासों से वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में एक अभूतपूर्व सफलता मिली है।

गुजरात के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया ने बताया कि कच्छ के अबडासा क्षेत्र में एक दशक के लंबे अंतराल के बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी- गोडावण) के चूजे का जन्म हुआ है, जो हम सभी के लिए गर्व का क्षण है।

वन मंत्री श्री मोढवाडिया ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि गुजरात वन विभाग ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के नेतृत्व में वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है।

उन्होंने इस उपलब्धि के लिए वाइल्ड लाइफ डिविजन के अधिकारियों के कार्यों की प्रशंसा की और इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी को बधाई दी।

इस सफलता के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण मंत्रालय, गुजरात और राजस्थान तथा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (डब्ल्यूआईआई) के संयुक्त प्रयासों की सराहना की और एक्स पर इस बारे में जानकारी देते हुए सभी को बधाई दी।

वन मंत्री श्री मोढवाडिया ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि यह सफलता 'जम्पस्टार्ट एप्रोच' नामक नवाचारपूर्ण संरक्षण प्रयासों के माध्यम से संभव हुई है।

पृष्ठभूमि और प्रोजेक्ट जीआईबी

गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 2011 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी-गोडावण) पक्षी को उसके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करने की परिकल्पना के अनुरूप वर्ष 2016 में 'प्रोजेक्ट जीआईबी' शुरू किया गया। नतीजतन, राजस्थान के सम और रामदेवरा में स्थापित ब्रीडिंग सेंटरों में पक्षियों की संख्या बढ़कर अब 73 तक पहुंच गई है।

कैसे मिली सफलता, (ऑपरेशन एग ट्रांसफर)

कच्छ में जीआईबी (गोडावण) की आबादी में नर पक्षियों की अनुपस्थिति के कारण मादा गोडावण अंडे तो देती थी, लेकिन वे निष्फल (इन्फर्टाइल) रहते थे। इस समस्या के समाधान के लिए एक साहसिक अभियान शुरू किया गया।

ट्रांस-स्टेट यात्रा

राजस्थान के ब्रीडिंग सेंटर से जीआईबी (गोडावण) का एक उर्वर अंडा लिया गया। इस अंडे को 19 घंटे की सड़क यात्रा के माध्यम से पोर्टेबल इनक्यूबेटर में सुरक्षित रूप से कच्छ लाया गया।

नेस्ट रिप्लेसमेंट

22 मार्च को कच्छ की मादा जीआईबी (गोडावण) के घोंसले में निष्फल अंडे के बदले इस उर्वर अंडे को रखा गया। मादा गोडावण ने इस अंडे को प्राकृतिक रूप से सेया और 26 मार्च को उससे स्वस्थ चूजे का जन्म हुआ।

भविष्य की योजना

फिलहाल फील्ड मॉनिटरिंग टीम मादा गोडावण और उसके बच्चे की लगातार निगरानी कर रही है।

वन मंत्री श्री मोढवाडिया ने कहा कि यह वैज्ञानिकों, वन विभाग के अधिकारियों और वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक गौरव का क्षण है, जो भारत के वन्यजीव पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को और मजबूत करता है।

खेड़ब्रह्मा - वडाली रेलखंड पर टेस्ट टिकट जारी,नई रेल सेवा शुभारंभ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

अहमदाबाद मंडल, पश्चिम रेलवे द्वारा अवगत कराया जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दिनांक 31 मार्च, 2026 को गुजरात राज्य में 891 करोड़ लागत की विभिन्न महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं का लोकार्पण एवं राष्ट्र को समर्पण करेंगे। इन परियोजनाओं के अंतर्गत खेड़ब्रह्मा – हिम्मतनगर – अहमदाबाद (असारवा) के मध्य नई ट्रेन सेवा का शुभारंभ तथा खेड़ब्रह्मा – हिम्मतनगर रेलखंड का राष्ट्र को समर्पण शामिल है। इसी क्रम में, आज दिनांक 28 मार्च, 2026 को खेड़ब्रह्मा से वडाली तक का सफलतापूर्वक 10 मूल्य का टेस्ट टिकट जारी कर परिचालन की परीक्षण प्रक्रिया पूर्ण की गई, जो इस नई रेल सेवा के शुभारंभ की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह परीक्षण यात्रियों के लिए टिकटिंग व्यवस्था, परिचालन प्रणाली एवं सुविधाओं की तैयारियों का सफल आकलन दर्शाता है। दिनांक 31 मार्च, 2026 को नई ट्रेन सेवा के शुभारंभ से पूर्व, स्थानीय सांसद एवं विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण 11वीं शताब्दी के प्राचीन ब्रह्मा मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे तथा तत्पश्चात रेलवे स्टेशन पर भी विधिवत पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। खेड़ब्रह्मा, उत्तर गुजरात के साबरकांठा जिले में स्थित एक प्राचीन एवं पवित्र धार्मिक नगरी है, जिसे ब्रह्माक्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह स्थान भगवान ब्रह्मा, ऋषि भृगु एवं माँ अंबिका से जुड़ी आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां स्थित प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर, जिसे स्थानीय रूप से "नाना अंबाजी" कहा जाता है, क्षेत्र की ग्रामदेवता के रूप में पूजित माँ अंबिका को समर्पित है। यह मंदिर अपनी प्राचीनता, आध्यात्मिक महत्व तथा समृद्ध आदिवासी संस्कृति के कारण विशेष पहचान रखता है। मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक मारु-गुर्जर शैली में निर्मित है, जिसमें नक्काशीदार स्तंभ, गर्भगृह एवं शांत परिसर दर्शनीय हैं। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार यह क्षेत्र वह स्थान है जहां भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया था तथा देवी अंबिका ने असुरों का संहार कर साधुओं की रक्षा की थी। तभी से यह स्थल एक प्रमुख शक्ति उपासना केंद्र के रूप में विकसित हुआ। मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद, श्री वेद प्रकाश ने बताया कि यह नई रेल सेवा न केवल क्षेत्र के यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि धार्मिक पर्यटन, स्थानीय व्यापार एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को भी नई गति देगी।

आधुनिक को-वर्किंग सुविधा के साथ यात्रियों के प्रतीक्षा अनुभव को मिला नया आयाम

वडोदरा स्टेशन पर 'एयरपोर्ट जैसा अनुभव', गुजरात के पहले डिजिटल लाउंज का माननीय सांसद डॉ. हेमांग जोशी द्वारा उद्घाटन

यात्रियों की सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए, पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा वडोदरा रेलवे स्टेशन पर डिजिटल लाउंज / को-वर्किंग स्पेस विकसित किया गया है, जिसका आज माननीय सांसद डॉ. हेमांग जोशी एवं माननीय विधायक श्री केयूर रोकडिया द्वारा उद्घाटन किया गया।

यह सुविधा गुजरात में रेलवे स्टेशन पर अपनी तरह की पहली तथा भारतीय रेल पर मुंबई सेंट्रल के बाद दूसरी है, जो वडोदरा स्टेशन को आधुनिक यात्री सुविधाओं के नए स्तर पर ले जाती है।

इस अवसर पर माननीय सांसद डॉ. हेमांग जोशी ने बताया कि वडोदरा रेलवे स्टेशन पर आज 'विकसित वडोदरा से विकसित भारत' की झलक दिखाई देती है। जैसे एयरपोर्ट के अंदर VVIP लाउंज होता है, वैसी ही सुविधा अब वडोदरा रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध है। यात्री अब एक ही स्थान पर मीटिंग, चाय-नाश्ता और विश्राम जैसी सभी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। साथ ही, बहुत ही किफायती दरों पर शॉवर और वॉशरूम की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह वडोदरा के लिए एक महत्वपूर्ण और गर्व का कदम है।

माननीय विधायक श्री केयूर रोकडिया ने कहा कि वास्तव में, पहली बार वडोदरा रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। आने वाले समय में बुलेट ट्रेन की कनेक्टिविटी, नए फीचर्स का समावेश तथा कार्गो के लिए अलग डेक जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

इस अवसर पर वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने बताया कि माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के मार्गदर्शन में वडोदरा स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की

दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए इसे पश्चिम रेलवे के सबसे स्वच्छ स्टेशनों में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में, 'उत्तम स्वच्छ स्टेशन' अभियान को आगे बढ़ाते हुए, एनएफआर पहल के अंतर्गत इस डिजिटल लाउंज की योजना बनाई गई है। वडोदरा के बरगद वृक्ष थीम पर आधारित यह लाउंज अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और यह यात्रियों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करेगा।

उन्होंने आगे बताया कि वडोदरा एक प्रमुख कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एवं बिज़नेस हब होने के साथ-साथ एकतानगर एवं धार्मिक स्थलों के कारण यात्रियों का प्रमुख केंद्र है। आने वाले समय में स्टेशन पर 18 महीनों में 4 नए पैदल ऊपरी पुल, दिव्यांगजन सुविधाओं में सुधार तथा हाई-स्पीड ट्रेन कनेक्टिविटी जैसी कई परियोजनाओं पर कार्य किया जाएगा, जिससे यात्रियों को और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री नरेन्द्र कुमार ने बताया कि यह डिजिटल लाउंज आधुनिक यात्रा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है, जिसमें हाई-स्पीड वाई-फाई, कार्य-स्टेशन, चार्जिंग पॉइंट, आरामदायक बैठने की व्यवस्था तथा कॉन्फ्रेंस सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, यात्रियों को प्रिंटिंग, स्कैनिंग, फोटोकॉपी, चाय-नाश्ता एवं पेय पदार्थों की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

यात्रियों के लिए लचीली उपयोग योजनाएं, जैसे अल्पावधि बैठने की सुविधा, प्रति घंटे कार्य-स्थल उपयोग, विस्तारित लाउंज पैकेज, मीटिंग रूम बुकिंग तथा पे-पर-यूज़ सेवाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही, अधिक आराम के लिए लाउंजर/रिक्लाइनर सीटिंग की सुविधा भी प्रदान की गई है।

यह डिजिटल लाउंज 24x7 संचालित होगा और इसमें रियल-टाइम ट्रेन सूचना प्रदर्शन, सीसीटीवी निगरानी, नियंत्रित प्रवेश, उन्नत शौचालय एवं कैशलेस भुगतान प्रणाली उपलब्ध होगी। स्वच्छता, सुरक्षा एवं पर्यावरणीय मानकों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

यह पहल वडोदरा रेलवे स्टेशन को आरामदायक, आधुनिक और उत्पादक यात्रा अनुभव प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और पश्चिम रेलवे की यात्री-केंद्रित सेवाओं को नई ऊंचाई देगा।

अफवाहों के बीच भरोसे की बात: देश में ईंधन आपूर्ति पूरी तरह सामान्य

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक स्तर पर उठ रही चिंताओं के बीच देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर फैल रही आशंकाओं पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। कंपनी ने साफ शब्दों में कहा है कि देश में कहीं भी ईंधन की कमी नहीं है और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य और संतुलित बनी हुई है।

हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, खासकर ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच हालात को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ी है। इन परिस्थितियों का असर वैश्विक तेल आपूर्ति पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इसी के चलते देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ देखने को मिली, जिससे लोगों के मन में ईंधन संकट की आशंका और गहरा गई।

इन सभी आशंकाओं को दूर करते हुए HPCL ने कहा कि देशभर में उसके सभी फ्यूल स्टेशन सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं और कहीं भी सप्लाई में कोई बाधा नहीं आई है। कंपनी के अनुसार, भारत की रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और पेट्रोल, डीजल तथा एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। न केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, बल्कि भविष्य की आपूर्ति को लेकर भी कोई खतरा नहीं है।

कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत का मजबूत रिफाइनिंग नेटवर्क लगातार ईंधन उत्पादन और वितरण को बनाए हुए है। देश में कई अत्याधुनिक रिफाइनरियां हैं, जो कच्चे तेल को प्रोसेस कर बड़े पैमाने पर ईंधन तैयार करती हैं। यही कारण है कि वैश्विक स्तर पर चाहे जितनी भी अनिश्चितता क्यों न हो, भारत अपनी आंतरिक जरूरतों को संतुलित ढंग से पूरा करने में सक्षम है। HPCL ने पेट्रोल पंपों पर देखी गई भीड़ को लेकर कहा कि यह स्थिति वास्तविक कमी के कारण नहीं, बल्कि गलत जानकारी यानी मिसइन्फॉर्मेशन के चलते उत्पन्न हुई। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से फैली अफवाहों ने लोगों को चिंतित कर दिया, जिसके चलते उन्होंने जरूरत से ज्यादा ईंधन खरीदना शुरू कर दिया।

पश्चिम रेलवे चलाएगी पाँच स्पेशल ट्रेनें

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा उनकी यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए विभिन्न गंतव्यों के बीच विशेष किराये पर पाँच स्पेशल ट्रेनें चलाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

1. ट्रेन संख्या 02200/02199 बांद्रा टर्मिनस–वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी सुपरफास्ट स्पेशल [30 फेरे]

ट्रेन संख्या 02200 बांद्रा टर्मिनस – वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्पेशल प्रत्येक शनिवार 05:10 बजे बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान कर अगले दिन 05:00 बजे वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पहुँचेगी। यह ट्रेन 04 अप्रैल, 2026 से 11 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 02199 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक गुरुवार 16:50 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 16:10 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 02 अप्रैल, 2026 से 09 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम, नागदा, उज्जैन, मक्सी, बियावरा राजगढ़, चाचौड़ा बीनागंज, रुठियाई, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, डबरा एवं दतिया स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, एसी 3-टियर (इकोनॉमी), स्लीपर क्लास तथा जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

2. ट्रेन संख्या 04126/04125 बांद्रा टर्मिनस – सूबेदारगंज सुपरफास्ट स्पेशल [30 फेरे]

ट्रेन संख्या 04126 बांद्रा टर्मिनस – सूबेदारगंज स्पेशल प्रत्येक मंगलवार 11:15 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 17:00 बजे सूबेदारगंज पहुँचेगी। यह ट्रेन 07 अप्रैल, 2026 से 14 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04125 सूबेदारगंज – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक सोमवार 05:20 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 09:30 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 06 अप्रैल, 2026 से 13 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना, रूपबास, फतेहपुर सीकरी, आगरा इडगाह, टुंडला, इटावा, गोविंदपुरी एवं फतेहपुर स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, एसी 3-टियर (इकोनॉमी), स्लीपर क्लास तथा जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

3. ट्रेन संख्या 05184/05183 बांद्रा टर्मिनस – आजमगढ़ सुपरफास्ट स्पेशल [30 फेरे]

ट्रेन संख्या 05184 बांद्रा टर्मिनस – आजमगढ़ स्पेशल प्रत्येक सोमवार 10:45 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 20:10 बजे आजमगढ़ पहुँचेगी। यह ट्रेन 06 अप्रैल, 2026 से 13 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 05183 आजमगढ़ – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक शनिवार 23:15 बजे प्रस्थान कर सोमवार को 08:10 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 04 अप्रैल, 2026 से 11 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, नागदा, कोटा, गंगापुर सिटी, बयाना, आगरा इडगाह, टुंडला, गोविंदपुरी, प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, ज्ञानपुर रोड, बनारस, औरीहर, मऊ एवं मोहम्मदाबाद स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी 3-टियर (इकोनॉमी), स्लीपर क्लास तथा जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

4. ट्रेन संख्या 05034/05033 बांद्रा टर्मिनस – गोमती नगर स्पेशल [30 फेरे]

ट्रेन संख्या 05034 बांद्रा टर्मिनस – गोमती नगर स्पेशल प्रत्येक मंगलवार 23:00 बजे प्रस्थान कर गुरुवार को 07:45 बजे गोमती नगर पहुँचेगी। यह ट्रेन 07 अप्रैल, 2026 से 14 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 05033 गोमती नगर – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक सोमवार 14:00 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 20:00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 06 अप्रैल, 2026 से 13 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, बयाना, आगरा इडगाह, टुंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग एवं बादशाहनगर स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास तथा जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

5. ट्रेन संख्या 05018/05017 वलसाड – मऊ स्पेशल [30 फेरे]

ट्रेन संख्या 05018 वलसाड – मऊ स्पेशल प्रत्येक रविवार 15:10 बजे वलसाड से प्रस्थान कर मंगलवार को 00:45 बजे मऊ पहुँचेगी। यह ट्रेन 05 अप्रैल, 2026 से 12 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 05017 मऊ – वलसाड स्पेशल प्रत्येक शनिवार 03:45 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 12:35 बजे वलसाड पहुँचेगी। यह ट्रेन 04 अप्रैल, 2026 से 11 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में सूरत, वडोदरा, रतलाम, नागदा, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, गंगापुर सिटी, बयाना, आगरा इडगाह, टुंडला, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बादशाहनगर, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया सदर, भटनी, सलेमपुर एवं बेल्थरा रोड स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास तथा जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 02200, 04126, 05184, 05034 एवं 05018 की बुकिंग 31.03.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं कोच संरचना की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

शहरों का होगा सर्वांगीण विकास, प्रधानमंत्री के करकमलों से रचा जाएगा नया इतिहास

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 31 मार्च को गुजरात के शहरों को देंगे 5295 करोड़ रुपए से अधिक की 44 विकास परियोजनाओं की सौगात

▸▸ अकेले अहमदाबाद में ही 4640 करोड़ रुपए की 32 परियोजनाओं का होगा लोकार्पण और शिलान्यास

▸▸ गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का 'अपने घर' का सपना होगा साकार : हजारों परिवारों को मिलेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान

▸▸ ऐतिहासिक नगरी वडनगर में हेरिटेज टाउन और सड़क सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट का होगा लोकार्पण

गांधीनगर : गुजरात के शहरी विकास के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 31 मार्च को अपने गुजरात दौरे के दौरान राज्य के शहरी क्षेत्रों में जनता की सुख-सुविधा में वृद्धि करने वाले तथा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की विभिन्न विकास-उन्मुख परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी शहरी विकास को बढ़ावा देने वाले राज्य के कुल 5295.54 करोड़ रुपए के 44 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 3427.14 करोड़ रुपए के 26 कार्यों का शिलान्यास और 1868.40 करोड़ रुपए के 18 कार्यों का लोकार्पण शामिल है।

इसके अंतर्गत, सबसे अधिक अहमदाबाद महानगर पालिका की 4640.12 करोड़ रुपए की 32 परियोजनाओं, जबकि गांधीनगर महानगर पालिका की 304.82 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं, गांधीनगर शहरी विकास प्राधिकरण की 272.86 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं तथा गुजरात अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की 77.74 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ऐतिहासिक नगरी वडनगर की विरासत को संरक्षित रखने और पर्यटन को गति देने के लिए 34.45 करोड़ रुपए के खर्च से 'हेरिटेज टाउन शहरी विकास और सड़क सौंदर्यीकरण' प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हाटकेश्वर मंदिर और संगीत संग्रहालय जैसे मुख्य स्थलों पर आधुनिक सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड लाइटिंग, सेंड स्टोन साइनेज और कलात्मक कृतियों से सौंदर्यीकरण किया गया है।

इसके साथ ही, प्रधानमंत्री पाटण में रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। पाटण शहर के लोगों की सुविधा के लिए 43.29 करोड़ रुपए की लागत से फाटक नंबर 41-ए (एलसी-41ए) पर 898 मीटर लंबा श्री-लेग रेलवे ओवरब्रिज तैयार किया गया है, जो यातायात की समस्या को दूर कर लगभग दो लाख लोगों को सुरक्षित और तेज यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा।

इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के मकानों का लोकार्पण करेंगे, जिससे हजारों परिवारों का 'अपने घर' का सपना साकार होगा। साथ ही साथ, अहमदाबाद के नए क्षेत्रों में ड्रेनेज और अन्य ढांचागत सुविधाओं की बड़ी परियोजनाएं आगामी समय में शहर का कायापलट करेंगी।

प्रधानमंत्री अहमदाबाद मनपा के इन विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास

1. खारीकट कैनाल डेवलपमेंट (पैकेज 1,2,3) – लोकार्पण – 811.27 करोड़ रुपए
2. निकोल-कठवाड़ा (टीपी-111) में 1100 ईडब्ल्यूएस आवास - लोकार्पण – 77.50 करोड़ रुपए
3. चिलोड़ा-नरोड़ा (टीपी-99) में 1017 ईडब्ल्यूएस आवास – लोकार्पण – 75.35 करोड़ रुपए
4. नरोड़ा-मुठिया (टीपी-71) में 470 ईडब्ल्यूएस आवास – लोकार्पण – 56 करोड़ रुपए
5. अमराईवाड़ी स्लम क्वार्टर्स में 672 आवास (पीपीपी) – लोकार्पण – 54.92 करोड़ रुपए
6. गोता (टीपी-33) में 448 ईडब्ल्यूएस आवास – लोकार्पण – 54.75 करोड़ रुपए
7. असारवा नॉर्थ (टीपी-30) पतरावाळी स्लम में 576 आवास – लोकार्पण – 47.93 करोड़ रुपए
8. हंसपुरा-नरोड़ा (टीपी-121) में 299 ईडब्ल्यूएस आवास – लोकार्पण – 35.59 करोड़ रुपए
9. वस्त्राल वार्ड (टीपी-114) में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण – लोकार्पण – 61.67 करोड़ रुपए
10 गोता-गोधावी कैनाल का आरसीसी बॉक्स कैनाल में रूपांतरण – लोकार्पण – 131.97 करोड़ रुपए
11. आकाश दर्शन सोसायटी के पास वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन – लोकार्पण – 25.08 करोड़ रुपए
12. दुधेश्वर वाटर वर्क्स में 20 मिलियन लीटर का टैंक – लोकार्पण – 31.07 करोड़ रुपए
13. भाड़ज (टीपी-406) में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन – लोकार्पण – 47.40 करोड़ रुपए
14. खारीकट कैनाल फेज-2 (रोपड़ा तालाब से खारी नदी तक) – शिलान्यास – 1061.43 करोड़ रुपए
15. बीआरटीएस और एएमटीएस के लिए आईटीएमएस सिस्टम प्रोजेक्ट 2.0 – शिलान्यास – 467 करोड़ रुपए
16. नारोल सर्कल से नरोड़ा पाटिया तक 14 किमी रोड़ डेवलपमेंट – शिलान्यास – 255.35 करोड़ रुपए
17. काजीमिया नो टेकरो (टीपी-3) में 728 आवास (पीपीपी) – शिलान्यास – 105.02 करोड़ रुपए
18. भागुभाई नी चाली (टीपी-3) में 595 आवास (पीपीपी) – शिलान्यास – 73.59 करोड़ रुपए
19 वटवा आउटफील्ड (टीपी-58) में 350 एलआईजी आवास – शिलान्यास – 66.18 करोड़ रुपए
20 नरोड़ा-हंसपुरा (टीपी-121) में 160 एलआईजी आवास – शिलान्यास – 38.80 करोड़ रुपए
21. वस्त्राल वार्ड में 1600 एमएम ड्रेनेज लाइन (माइक्रो टनलिंग) – शिलान्यास – 31.24 करोड़ रुपए
22 नरोड़ा वार्ड (टीपी-75) में नया ऑडिटोरियम – शिलान्यास – 86.29 करोड़ रुपए
23. रास्का में अतिरिक्त 100 एमएलडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट – शिलान्यास – 79.48 करोड़ रुपए
24 सीजी रोड में एडवांस फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी – शिलान्यास – 37.22 करोड़ रुपए
25 सुभाष ब्रिज का नवनिर्माण (4 लेन ब्रिज और 2 लेन ब्रिज) – शिलान्यास – 236 करोड़ रुपए
26. वेस्ट जोन में थिमैटिक प्रिसिंक्ट पैकेज-1 के विभिन्न रोड – शिलान्यास – 282.82 करोड़ रुपए
27. लोटस पार्क डेवलपमेंट (घाटलोडिया तालाब) – शिलान्यास – 128.85 करोड़ रुपए
28. नॉर्थ-वेस्ट जोन (टीपी-56, 151-ए आदि) में ड्रेनेज नेटवर्क – शिलान्यास – 42.93 करोड़ रुपए
29 नॉर्थ-वेस्ट जोन (टीपी-54, 55, 228 आदि) में ड्रेनेज नेटवर्क – शिलान्यास – 40.47 करोड़ रुपए
30 नॉर्थ-वेस्ट जोन (टीपी-40, 41, 53-ए आदि) में ड्रेनेज नेटवर्क – शिलान्यास – 28.42 करोड़ रुपए
31 हेबतपुर-थलतेज क्षेत्र में तालाबों को जोड़ने का नेटवर्क – शिलान्यास – 27.85 करोड़ रुपए
32 ओलंपिक-2036 के अंतर्गत नरेन्द्र मोदी स्टेडियम के निकट वाटर लाइन शिफ्टिंग – शिलान्यास – 40.68 करोड़ रुपए
प्रधानमंत्री गांधीनगर महानगर पालिका और गांधीनगर शहरी विकास प्राधिकरण के इन विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास
1 वासणा-हड़मतिया (टीपी-09) में 624 ईडब्ल्यूएस-2 आवासों का निर्माण – लोकार्पण – 80.50 करोड़ रुपए
2 वासणा-हड़मतिया (टीपी-09) में 1352 ईडब्ल्यूएस-2 आवासों का निर्माण – लोकार्पण – 165.54 करोड़ रुपए
3 मोटा चिलोड़ा (टीपी-17) में ड्रेनेज नेटवर्क और 7.0 एमएलडी एसटीपी – शिलान्यास – 26.82 करोड़ रुपए
4 जीएमसी क्षेत्र (टीपी-06) में वर्किंग वुमन हॉस्टल का निर्माण – शिलान्यास – 25.61 करोड़ रुपए
5 सेक्टर-11 बिजनेस कॉरिडोर रोड डेवलपमेंट और सौंदर्यीकरण – शिलान्यास – 25.53 करोड़ रुपए
6 रांधेजा में 4 तालाबों को जोड़ने और स्टॉर्म वाटर लाइन – शिलान्यास – 25.02 करोड़ रुपए
7 कोबा, रायसण, रांदेसण क्षेत्र में स्टॉर्म वाटर लाइन – शिलान्यास – 59.48 करोड़ रुपए
8 टीपी-29 से अडालज टीएसपीएस तक 1800 एमएम ड्रेनेज ट्रंक मेन – शिलान्यास – 62.15 करोड़ रुपए
9 कुडासण, रायसण, रांदेसण, सरगासण सहित अन्य गांवों में नए रोड – शिलान्यास 72.91 करोड़ रुपए
10 पेथापुर में 15 एमएलडी एसटीपी का निर्माण – लोकार्पण – 34.12 करोड़ रुपए

राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग ने इन सभी कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे दिया है। प्रधानमंत्री का यह दौरा गुजरात के शहरी बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ और आधुनिक बनाने की दिशा में क महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आगामी 31 मार्च को गुजरात में 891 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे

खेडब्रह्मा से हिंमतनगर होकर अहमदाबाद (असारवा) तक की नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आगामी 31 मार्च मंगलवार को गुजरात की एक दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान वे राज्य के नागरिकों को भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के 891 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट्स की भेंट देंगे। कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने, आर्थिक गतिविधियों को गति देने और यात्रियों की परिवहन सुविधा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री एक नई ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात में वाव-थराद से इन प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि रेलवे के ये प्रोजेक्ट्स गुजरात में रेल अवसंरचना के आधुनिकीकरण एवं क्षेत्रीय विकास को वेग देने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हैं। प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पित होने वाले रेलवे

प्रोजेक्ट्स

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हिंमतनगर से खेडब्रह्मा तक 55 किलोमीटर नई रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे, जिसका 482 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया गया है। इसके जरिये साबरकाँठा जिले में कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा, जो त्वरित एवं पोषक दर पर यात्रा सुनिश्चित करेगा और इस प्रोजेक्ट से अहमदाबाद को उदयपुर के साथ सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। अनुमान है कि इससे स्वास्थ्य शुश्रुषा तथा शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं की पहुँच में वृद्धि होगी और साथ ही साथ स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के नए अवसर भी सृजित होंगे।

इसके अलावा; 257 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कानालुस-जामनगर डबलिंग प्रोजेक्ट (27 किलोमीटर) अंतर्गत अतिरिक्त रेलवे लाइन तथा गांधीधाम-आदिपुर मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट (11 किलोमीटर) का भी प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। इन परियोजनाओं से ट्रेनों का आवागमन अधिक तेज एवं सुगम बनेगा। साथ ही साथ; माल-सामान की आवाजाही अधिक कार्यक्षम रूप से होगी और दीनदयाल पोर्टल सहित महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा। ये परियोजनाएँ स्थानीय पर्यटन विकास में भी योगदान देंगी।

इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री खेडब्रह्मा से अहमदाबाद तक की ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो वाया हिंमतनगर होकर चलेगी। यह ट्रेन शुरू होने से इस क्षेत्र में नागरिकों के लिए यात्रा अधिक तेज एवं सुगम बनेगी और स्थानीय आर्थिक विकास को वेग मिलेगा। प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार भारतीय रेलवे को आधुनिक तथा अधिक कार्यक्षम बनाने के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर नागरिकों के यात्रा अनुभव को समृद्ध बनाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इन पहलों से समावेशी विकास को प्रोत्साहन मिलेगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत बनेगी।

नई उड़ान का दौर: जेवर से उठी विकास की ऐतिहासिक शुरुआत

उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी में एक नया अध्याय उस समय जुड़ गया, जब नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रथम चरण का उद्घाटन किया। यह सिर्फ एक एयरपोर्ट का उद्घाटन नहीं था, बल्कि यह उस बदलते भारत की तस्वीर थी, जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नोएडा के जेवर क्षेत्र में बना यह एयरपोर्ट आज देश की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल हो चुका है, जिसने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास को नई दिशा देने का काम किया है।

करीब 5,000 हेक्टेयर में फैला यह विशाल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट 30,000 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार हो रहा है। इसका निर्माण चार चरणों में किया जाना है, जिसमें पहले चरण पर लगभग 10,000 से 12,000 करोड़ की लागत आई है और यह अब संचालन के लिए तैयार हो चुका है। पहले चरण में एक रनवे तैयार किया गया है, जबकि पूरी परियोजना पूरी होने के बाद यहां कुल छह रनवे होंगे। शुरुआती चरण में यह एयरपोर्ट लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों को प्रतिवर्ष संभालने में सक्षम होगा, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 7 से 8 करोड़ यात्रियों तक किया जा सकता है।

यह एयरपोर्ट भारत का एक प्रमुख ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, जिसे अत्याधुनिक तकनीक और मल्टी-फेज विकास योजना के साथ तैयार किया गया है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर के मौजूदा एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को गति देना है। इसके साथ ही यह क्षेत्रीय रोजगार, व्यापार और निवेश के नए अवसर भी पैदा करेगा।

उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक परिस्थितियों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में पिछले एक महीने से चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। इस संघर्ष के कारण कई देशों में खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरकों की कमी जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत भी इस चुनौती से अछूता नहीं है, लेकिन देश अपनी पूरी क्षमता और दृढ़ता के साथ इस संकट का सामना कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने देशवासियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि जनता की ताकत ही भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। इसी विश्वास के सहारे देश इन कठिन परिस्थितियों में भी मजबूती से खड़ा है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार हर संभव कदम उठा रही है ताकि इस वैश्विक संकट का असर आम लोगों और किसानों पर कम से कम पड़े।

कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए यह क्षण विशेष है, क्योंकि उन्हें इस एयरपोर्ट का शिलान्यास करने का भी अवसर मिला था और अब उद्घाटन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बन गया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।

उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को विशेष बधाई देते हुए कहा कि यह एयरपोर्ट केवल विमानों के उड़ान भरने का केंद्र नहीं होगा, बल्कि यह पूरे क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

गिफ्ट सिटी : भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल और आईटी हब

▸▸ आज गिफ्ट सिटी में 1150 से अधिक आईएफएससीए-रजिस्टर्ड संस्थान संचालित

▸▸ गिफ्ट सिटी में बैंकिंग क्षेत्र 106 बिलियन डॉलर तक पहुंचा, पूंजी बाजार 80 बिलियन डॉलर तक पहुंचा

गांधीनगर, 28 मार्च : गांधीनगर स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) भारत के पहले संपूर्ण रूप से संचालित वैश्विक फाइनेंशियल और आईटी हब के रूप में उभरा है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इकोसिस्टम में देश को अग्रिम कतार में खड़ा रखता है।

गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में स्थापित की गई गिफ्ट सिटी आज एक समृद्ध, नीति-संचालित और वैश्विक स्तर पर ऐतिहासिक वित्तीय केंद्र में परिवर्तित हो गई है।

प्रारंभ से ही, गिफ्ट सिटी की परिकल्पना एक विश्वस्तरीय फाइनेंस और आईटी जोन के रूप में की गई थी। एक ऐसा वित्तीय केंद्र जो न केवल भारत को, बल्कि पूरी दुनिया को सेवाएं प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एक ऐसे एकीकृत इकोसिस्टम की नींव रखी गई, जो वित्तीय सेवाओं, टेक्नोलॉजी, विनियामक सुगमता और ढांचागत सुविधाओं को एक ही अधिकार क्षेत्र के भीतर जोड़ता है। उनका विजन अब एक जीवंत केंद्र मंक परिवर्तित हो गया है, जो स्थापित वैश्विक वित्तीय केंद्रों के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा करता है।

आज मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गिफ्ट सिटी की क्षितिजों का विस्तार हो रहा है, और वे उसी प्रतिबद्धता के साथ गिफ्ट सिटी की निरंतरता, विस्तार और तेज विकास को सुनिश्चित कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में गिफ्ट सिटी ने नई ऊंचाइयां छुई हैं, जो भारत के आर्थिक विकास के प्रेरक बल के रूप में गुजरात की प्रतिष्ठा को मजबूत बनाती है।

आज गिफ्ट सिटी में 1150 से अधिक आईएफएससीए-रजिस्टर्ड (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण में पंजीकृत) संस्थान कार्यरत हैं। गिफ्ट सिटी में बैंकिंग

क्षेत्रों का भी उल्लेखनीय विकास हुआ है, जो 106 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यह 2020 की तुलना में लगभग सात गुना वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा, पूंजी बाजार (कैपिटल मार्केट) भी 80 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और हर महीने एक्सचेंज टर्नओवर लगातार 100 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, 80 बिलियन डॉलर के लक्ष्य के साथ 349 फंड्स शुरू किए गए हैं, जो वैश्विक पूंजी बाजारों में भारत की स्थिति को और अधिक मजबूत बनाते हैं।

गिफ्ट सिटी का विकास केवल वित्तीय गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक गिफ्ट सिटी में वर्ष 2030 तक 1,00,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है, जिसमें कमर्शियल (व्यापारिक), रेजिडेंशियल (रिहायशी) और इंस्टीट्यूशनल (संस्थागत) निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार का बड़ा योगदान होगा।

इसके साथ ही, गिफ्ट सिटी में एक मजबूत सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण किया गया है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्कूल, डेस्टिनेशन मॉल, सेंट्रल पार्क और स्पोर्ट्स एरिना आदि शामिल हैं। गिफ्ट सिटी में रहने वाले लोगों और काम करने वाले पेशेवरों, दोनों के लिए 'लिव, वर्क, थ्राइव' यानी जिएं, काम करें और समृद्ध बनें के मंत्र के साथ इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण किया गया है।

गिफ्ट सिटी में अत्याधुनिक ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारत में पहली बार यहां अंडरग्राउंड यूटिलिटी टनल स्थापित की गई है। इसके अलावा, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और ऑटोमैटेड वेस्ट कलेक्शन के जरिए कुशल और टिकाऊ परिचालन सुनिश्चित किए जाते हैं। वैश्विक स्तर पर, गिफ्ट सिटी भारत के अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल गेटवे के रूप में काम करता है, जिसकी पहुंच दावोस में विश्व आर्थिक मंच जैसे कार्यक्रमों और मिलान, ज्यूरिक, हांगकांग, जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे प्रमुख वित्तीय केंद्रों तक है। भारत में, यह बैंकिंग फोरम (100 से अधिक संस्थानों के साथ), वाइब्रेंट गुजरात, आईजीएफ मुंबई और रिइंश्योरेंस समिट के साथ समन्वय बनाकर स्थानीय और वैश्विक वित्तीय नेटवर्क को एक साथ लाता है।

गिफ्ट सिटी में एक ही छत के नीचे विभिन्न वित्तीय सेवाएं मिलती हैं, जिनमें पूंजी बाजार, बैंकिंग, बीमा, विमान और जहाज लीजिंग सेवाएं, फिनटेक, जीसीसी और वैश्विक यूनिवर्सिटियों के साथ साझेदारी शामिल हैं। यह 37 से अधिक बैंकों, 65 से अधिक बीमा कंपनियों और 35 से अधिक एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनियों के साथ एक उच्च-मूल्य वाली वित्तीय सेवाओं के एक विश्वसनीय केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है और वैश्विक वित्तीय इकोसिस्टम में भारत की स्थिति को और मजबूत बनाने में सहयोग कर रहा है।

गिफ्ट सिटी की शुरुआत श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में की गई थी और गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में इसका लगातार विकास किया गया है। यह भारत को वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करने के रणनीतिक और दीर्घकालिक विजन को प्रतिबिंबित करता है।

10 जून से पोरबंदर–दादर दैनिक सौराष्ट्र एक्सप्रेस की कोच संरचना में परिवर्तन

यात्रियों की बढ़ती मांग एवं उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा ट्रेन संख्या 19016/19015 पोरबंदर–दादर–पोरबंदर दैनिक सौराष्ट्र एक्सप्रेस की कोच संरचना में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में चल रही सेकंड एसी कम थर्ड एसी (2AC cum 3AC) कोच के स्थान पर अब अलग-अलग एक सेकंड एसी (2AC) तथा एक थर्ड एसी (3AC) कोच लगाए जाएंगे। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा एवं अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।

यह संशोधित कोच संरचना निम्नानुसार प्रभावी होगी:

▸▸ ट्रेन संख्या 19016 पोरबंदर–दादर दैनिक सौराष्ट्र एक्सप्रेस में 10 जून, 2026 से

▸▸ ट्रेन संख्या 19015 दादर–पोरबंदर दैनिक सौराष्ट्र एक्सप्रेस में 13 जून, 2026 से

▸▸ यात्रियों अपनी यात्रा से पूर्व ट्रेनों के संचालन एवं कोच संरचना की अद्यतन जानकारी NTES App, Indian Railways की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in अथवा रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

अविरत गुजरात, विकसित गुजरात

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी साणंद और नरोड़ा जीआईडीसी की 271 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे

▸▸ साणंद में बारिश में जलजमाव की समस्या का स्थायी हल : 244 करोड़ रुपए के खर्च से आरसीसी स्टॉर्म वाटर ड्रेन प्रोजेक्ट पूर्ण

▸▸ इस प्रोजेक्ट से साणंद औद्योगिक क्षेत्र अब 'जीरो वाटर लॉगिंग' जोन बनेगा

▸▸ नरोड़ा औद्योगिक क्षेत्र का 27.20 करोड़ रुपए के खर्च से नवीनीकरण : आधुनिक ढांचागत सुविधाओं से उद्योगों को मिलेगा बूस्ट

▸▸ प्रधानमंत्री 31 मार्च को गुजरात की औद्योगिक क्षमता को बल देने वाली परियोजनाएं जनता को समर्पित करेंगे

गांधीनगर : 'विकसित गुजरात से विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने के मंत्र के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 31 मार्च, 2026 को गुजरात के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे के दौरान वे अहमदाबाद के साणंद शहर से गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) द्वारा पूरी की गई 271.20 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। अहमदाबाद जिले के साणंद में लगभग 2056 हेक्टेयर में फैला औद्योगिक क्षेत्र आज सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल और फार्मास्युटिकल्स जैसे हाई-टेक उद्योगों का हब बन गया है। यहां 1150 से अधिक इकाइयां कार्यरत हैं। मानसून के दिनों में इस क्षेत्र में होने वाली जमजमाव की गंभीर समस्या के स्थायी हल के लिए जीआईडीसी ने दो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पूरे किए हैं।

इनमें पूर्व और पश्चिम ड्रेन प्रोजेक्ट के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र के दोनों ओर 18.71 किमी लंबी आरसीसी स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाई गई है, जो आंतरिक और ऊपरी क्षेत्र के पानी की निकासी करेगी। इसके अलावा, साणंद-वीरमगाम हाईवे के मुख्य प्रवेशद्वारों के पास 18.35 किमी लंबी ड्रेन सिस्टम तैयार किया गया है।

मार्च-2026 में पूरे हुए इस प्रोजेक्ट से साणंद औद्योगिक क्षेत्र अब 'जीरो वाटर लॉगिंग' जोन बनने की ओर आगे बढ़ रहा है।

1963 में स्थापित राज्य की सबसे बड़ी औद्योगिक बसाहटों में से एक नरोड़ा औद्योगिक क्षेत्र को भी राज्य सरकार की 'असिस्टेंस फॉर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर (एआईआई)' योजना के तहत नया कलेवर दिया गया है। यहां 27.20 करोड़ रुपए के खर्च से विभिन्न कार्य पूरे किए गए हैं। इसके अंतर्गत, आंतरिक सड़कों का मजबूतीकरण और विस्तार, स्टॉर्म वाटर ड्रेन और प्राकृतिक नाले की लाइनिंग, 1.19 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में पेवर ब्लॉक, फुटपाथ और पार्किंग की सुविधा तथा नई स्ट्रीट लाइट्स, हाई-मास्ट लाइट्स, सिक्योरिटी केबिन और टॉयलेट ब्लॉक्स का निर्माण किया गया है।

इन परियोजनाओं के लोकार्पण से साणंद और नरोड़ा के हजारों लघु और बड़े उद्योगों को सीधा फायदा होगा। आधुनिक ड्रेन सिस्टम, स्मार्ट वाटर मीटर, सीसीटीवी सर्विलांस और सड़कों के मजबूतीकरण के कारण माल-सामान की आवाजाही आसान हो जाएगी और गुजरात वैश्विक निवेशकों के लिए और भी आकर्षक बन जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों से विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी सहित मंत्रिमंडल के सदस्य और अग्रणी उद्योगपति मौजूद रहेंगे।